ई-मैगज़ीन : www.worldfamenews.com
वर्ष 7 अंक 10
नवम्बर 2016 मूल्य ₹ 30/-

हिम्मत ना हारना, हम साथ हैं आपके

WORLD FAME NEWS

एमी ने मुर्गियों पर जताया प्यार

छवि बदलने को फिर वही पैंतरा

उत्तर प्रदेश आसान नहीं जंग

चीन-पाकिस्तान की खतरनाक दोस्ती

बेघर और बीमार हुईं बांझ गायें

भारत को उकसाना बंद करे पाकिस्तान

विश्व की 10 सबसे ताकतवर सेनाएं

खबरदार - वर्ल्ड फेम की निगाह हर तरफ.......

हम है सबसे तेज,

क्योंकि हम पढ़ते हैं देश में तेजी से बढ़ रही

वर्ल्ड फेम न्यूज मैग्ज़ीन

SUBSCRIBE NOW

Log on www.worldfamenews.com

WORLD FAME

ONLINE MAGAZINE

News Updates & Much More ....

visit us at : www.worldfamenews.com

एडीटर-इन-चीफ :- देवेन्द्र कुमार सक्सैना
मैनेजिंग एडीटर :- सुनील कुमार भटनागर
चीफ एक्जीक्यूटिव एडीटर :- हरेन्द्र कुमार सक्सैना
एक्जीक्यूटिव एडीटर :- के.जी. सक्सैना
गेस्ट एडीटर :- डा. मृदुला कठेरिया
न्यूज एडीटर :- रविन्द्र पाल (प्रवीन)
फीचर एडीटर :- अंजुल कुलश्रेष्ठ
सीनियर सब एडीटर :- श्री कृष्ण शर्मा
एसोसिएट एडीटर :- आर.एन. त्यागी
एसोसिएट एडीटर :- विनोद कटियार
सब एडीटर :- सुलभ कुलश्रेष्ठ
हैड (न्यूज सेक्शन) :- दीपक कुमार सक्सैना
प्रभारी लीगल सेक्शन :- श्री कृष्ण शर्मा एडवोकेट
प्रभारी संपादकीय कार्या. :- रविन्द्र पाल (प्रवीन)
जनसंपर्क अधिकारी :- शीतल वर्मा
जनरल मैनेजर :- आशीष तिवारी
ब्यूरो चीफ (मथुरा) :- मनोज शर्मा
सिटी इंचार्ज/रिपोर्टर :- सौरभ तेनगुरिया

एडवाइजरी बोर्ड
*इंजी. आर.एस. सक्सैना *मुकेश कुमार शर्मा एड.
*किशन गोपाल तिवारी *नीरज श्रीवास्तव

ऑलीवुड फिल्म सोसायटी के सहयोग से स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक – देवेन्द्र कुमार सक्सैना द्वारा जय दुर्गा प्रिन्टर एण्ड पब्लिशर 19/8/2, ए गली नं. 1 खतैना रोड़ लोहामण्डी, आगरा (उ0 प्र0) से मुद्रित एवं 3/218, रूई की मण्डी, शाहगंज, आगरा (उ0 प्र0) से प्रकाशित, सम्पादक – देवेन्द्र कुमार सक्सैना

सम्पादकीय कार्यालय : बी–8, वी.एस. टॉवर, आवास विकास, सेक्टर–3ए, सिकन्दरा, आगरा–282007 (उ0प्र0)
E-mail : worldfamenews@gmail.com
Phone : 0562-4030963, Mob.: +91-9058904297

पत्रिका सम्बधी सर्वाधिकार सुरक्षित है। किसी भी रूप में प्रकाशित सामग्री की नकल प्रतिबंधित है पत्रिका में छपे किसी भी लेख के लिए संपादक/प्रकाशक/स्वामी उत्तरदायी नहीं है, पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए लेखक स्वंय जिम्मेदार हैं। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री या विज्ञापन से संपादक/प्रकाशक/स्वामी का सहमत होना अनिवार्य/आवश्यक नहीं है, इससे सम्बधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही या पूँछताछ प्रकाशन तिथि से तीन माह के अन्दर की जा सकती है। तीन माह पश्चात किसी भी प्रकार की कार्यवाही या पूछताछ का उत्तर देने के लिए हम वाध्य नहीं है, प्रेषित स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जायेगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र आगरा होगा।

– वैधानिक चेतावनी –

पाठकों को सलाह दी जाती है किसी विज्ञापन पर किसी भी प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में अपनी पूरी तरह से जाँच पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र/पत्रिका उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता या विज्ञापन दाता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापन द्वारा किये गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। इसमें प्रकाशित किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले विज्ञापन के बारे में पूर्ण जाँच पड़ताल कर लें तब आगे बढ़े। समाचार पत्र/पत्रिका उपरोक्त किसी भी विज्ञापन के बारे में किसी भी पाठक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

सभी पद अवेतनिक है।

सबके मालिक/सूक्ष्म संरक्षक
साँई बाबा

प्रेरणा स्त्रोत/सूक्ष्म संरक्षक
माँ सुशीला देवी

संस्थापक/सूक्ष्म संरक्षक
उमा शंकर सक्सैना

वर्ल्ड फेम न्यूज

वर्ष : 07
अंक : 10
नवम्बर : 2016

इस अंक में

- संपादकीय 04
- खाते में सेंध लग लाए तो... 10
- व्यक्तित्व विकास के 10 जबरदस्त.. 23
- खूब सूरत दिखने के आसान... 24
- आशया शर्मा की हुई... 28
- पागलों की तरह प्यार में हूं.. 29
- गलतियों पर काम करना... 31
- आस्था वर्ल्ड 34

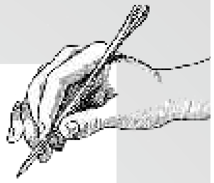

सामान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता का मतलब है हर नागरिक के लिए विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसे कानून। संविधान के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह कानून काफी हद तक विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव से संबंधित है। फिलहाल देश में हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग-अलग नागरिक कानून हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आदि धर्म आते हैं जबकि मुस्लिम व इसाई समुदाय का अपना-अपना पर्सनल लॉ है। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एकरूपता लाना है। हालांकि संविधान अनुच्छेद 44 के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना राज्यों की डयूटी है। लेकिन इसे अक्सर धर्मनिरपेक्षता की बहस में पटरी से उतार दिया जाता है। आजादी के 69 साल बाद भी इस पर आम सहमति नहीं बन पाई है। आजादी से 6 वर्ष पहले 1941 में ब्रिटिश सरकार ने बीएन राव की अध्यक्षता में हिन्दू लॉ कमेटी का गठन किया था।

कई वर्षो की जद्दोजहद के बाद अखिरकार वर्ष 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 में हिन्दू दत्तक ग्रहण रखरखाव अधिनियम तथा 1956 में ही हिन्दू अल्पसंख्यक तथा संरक्षण अधिनियम पारित हुए। इन कानूनों के जरिए महिलाओं के सीधे तौर पर सशक्त बनाया गया। हालांकि, तब से लेकर अब तक इनमें कई संशोधन किए जा चुके हैं, और धर्मो के पर्सनल लॉ को जस का तस रहने दिया गया। और कहा गया अगर समान नागरिक संहिता लागू की गई सभी धर्मो के ऊपर हिन्दू कानून लागू हो जाएगा और धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी।

संविधान की प्रस्तावनर और उसका अनुच्छेद 44 में भी कहता है कि एक समान नागरिक संहिता की जरूरत है। इस पर व्यापक विचार-विमर्श करने की जरूरत है। लेकिन हकीकत सबके सामने है। इस संहिता का स्वरूप क्या हो, यह भी परिभाषित नहीं किया जा सका है। देश के शासकों ने अंग्रेजों द्वारा नागरिक कानूनों में किए निजी एवं सार्वजनिक बंटवारे को ही आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमनल जस्टिस सिस्टम बनाया जो अभी भी लागू है। सिविल लॉ के बारे में 1840 में ऐसे प्रयास किए गए, हिन्दुओं सहित सभी धर्मावलंबिलों के विरोध के बाद कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो सका।

देवेन्द्र कुमार सक्सैना

Write : dksaxena09@gmail.com

उत्तर प्रदेश : आसान नहीं जंग

—रविन्द्र पाल (प्रवीन)

उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव सपा और बीएसपी के लिए वजूद की बेताब लड़ाई और कांग्रेस के लिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की जंग होगी। वहीं बीजेपी के लिए, जिसने महज तीन से भी कम साल पहले राज्य की ज्यादातर सीटें अपनी झोली में डालकर राष्ट्रीय बहुमत हासिल किया था, अपने केंद्रीय नेतृत्व पर जनमत संग्रह होगा। यह मुलायम और मायावती के सफर का अंत, मुश्किलों से घिरे राहुल के लिए आखिरी तिनका और मोदी के लिए सियासी संकट की शुरुआत हो सकता है, जिनकी पार्टी को पिछले साल बिहार और दिल्ली में भारी हार का मुंह देखना पड़ा था।

उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर रह गए हैं। राजधानी लखनऊ में लोकतंत्र के अगले उत्सव की तैयारी में साज-सज्जा शुरू हो गई है। हवाई अड्डे के बाहर लखनऊ मेट्रो के खंभों को चमकाया जा रहा है, चारबाग रेलवे स्टेशन तक उसकी परीक्षण यात्रा जो होने वाली है। शहर के भीतर ड्राइव करते समय रिंग रोड-जिसे आजादी के आंदोलन के शहीदों के सम्मान में शहीद पथ कहा जाता है नई बनी कॉलोनियों के हजारों गगनचुंबी अपार्टमेंट के साथ आसमान की ओर एक नया नजारा पेश करती है। नामपट्टों को सजाया-संवारा जा रहा है जो आपको चाक गंजरिया में बन रही आइटी सिटी का रास्ता बताते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी, जो इकाना स्पोर्ट्स सिटी में बन रहा है। शहर की जीवनरेखा गोमती नदी में भी नए घाट बनाए जा रहे हैं। कहीं लोग भूल न जाएं कि इसके लिए किसका शुक्रिया अदा करना है, इसलिए बड़े-बड़े कटआउट इन विकास परियोजनाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये कटआउट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम, उनके चाचा शिवपाल और साथ ही गद्दीनशीन समाजवादी पार्टी (सपा) को नियंत्रित करने वाले यादव कुनबे के बहुत सारे चचेरे-ममेरे भाई-बहनों, चाचाओं, चाचियों और बहुओं के हैं।

लखनऊ के बीचोबीच, अपनी हुकूमत के दौरान बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की नेता मायावती के बनवाए गुलाबी बलुआ पत्थर के स्मारकों को विशालकाय होर्डिंग घेरे हुए हैं, जिन पर वे दोबारा धमाके के साथ सत्ता में लौटने का वादा करती दिखाई दे रही हैं। इन पर उदारता से इस्तेमाल की गई दलित मसीहा बी. आर. आंबेडकर और उनके पूर्व मार्गदर्शक कांशीराम की तस्वीरों के साथ सलवार-सूट पहने, हैंडबैग थामे 'दलित की बेटी' पांच साल के 'वनवास' से लौट आई हैं और 'कमजोर' अखिलेश से लेकर 'गायब' कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक को, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, जिनकी हुकूमत 'नाकामियों से तार-तार' है, चुनौती देने के लिए तैयार हैं।

राहुल सूबे भर की खाट यात्रा पर निकले हुए हैं और चर्चा का विषय बन गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौरान वे बन गए थे। हालांकि संदर्भ बदल गया है। उस वक्त सत्तारूढ़ यूपीए-2 की हुकूमत की नुमाइंदगी करने के बजाए राहुल उस एकमात्र भूमिका में हैं जिसमें वे सबसे ज्यादा रचे-बचे दिखाई देते हैं विद्रोही, बाहरी आदमी की भूमिका, हालांकि उनके खानदान को देखते हुए यह बिल्कुल गैर या पराये की भूमिका भी नहीं है। अपने बगल में रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लिए राहुल, अखिलेश और मायावती को मोदी के 'रिमोट कंट्रोल से चल रहा' बताकर निशाना साध रहे हैं और इसके साथ ही मोदी के खिलाफ अपने तीरों से चुनावी कड़ाहे को खौलाने की उम्मीद कर रहे हैं।

और इस चौकोने मुकाबले में सबसे खामोश भारतीय जनता पार्टी 'बीजेपी' है, जिसकी अगुआई चालाक अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं, जिनका लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने राज्य मुख्यालय में आना-जाना काफी बढ़ गया है। 2014 में लोकसभा की 80 में से 73 सीटें जीतने की पटकथा रचकर एक बार वे अकल्पनीय कारनामा कर चुके हैं। नेपथ्य से काम कर रहे उनके लड़कों को पूरा भरोसा है कि बिजली दूसरी बार भी कौंधेगी। पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, 'टीम को लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग और बूथ का प्रबंधन दो साल पहले कामयाब हुआ था, वह इस बार भी कारगर होगा, भले ही मुख्यमंत्री पद का कोई दमदार उम्मीदवार न हो। 'राम मंदिर', 'गोमांस पर पाबंदी', 'घर वापसी' और 'लव जेहाद' सरीखे मुहावरे अभी तक पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहे हैं। मगर अभी तो खेल शुरू ही हुआ है।

घंटियां, सीटियां, झंडे, गुब्बारे, शेखियां, दिखावा, टीका-टिप्पणी, दांवपेच और तिकड़म ऊंचे दांव वाली इस लड़ाई की इत्तिला देते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव सपा और बीएसपी के लिए वजूद की बेताब लड़ाई और कांग्रेस के लिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की जंग होगी। वहीं बीजेपी के लिए, जिसने महज तीन से भी कम साल पहले राज्य की ज्यादातर सीटें अपनी झोली में डालकर राष्ट्रीय बहुमत हासिल किया था, अपने केंद्रीय नेतृत्व पर जनमत संग्रह होगा। यह मुलायम और मायावती के सफर का अंत, मुश्किलों से घिरे राहुल के लिए आखिरी तिनका और मोदी के लिए सियासी संकट की शुरुआत हो सकता है, जिनकी पार्टी को पिछले साल बिहार और दिल्ली में भारी हार का मुंह देखना पड़ा था।

चुनाव भले ही अभी पांच महीने दूर हों, पर देश के सबसे बड़े चुनाव अभियान की गर्द और सरगर्मी बढने लगी है। सपा के खेमे में मार-काट शुरू हो चुकी है। बीएसपी ने अपने पंजे नुकीले कर लिए हैं। कांग्रेस ने अपनी फौज में भर्ती की जबरदस्त मुहिम छेड़ दी है। बीजेपी अपने गुरिल्ला लड़ाकों को चुपचाप दाखिल कर रही है। इन सबका साझा मकसद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मतदाता मंडल को रिझाना, फुसलाना या धौंसियाना है, उस हिंदी पट्टी में जहां बेरहम चुनावी गणित कोई रियायत नहीं बख्शता। यह कोई लीग मैच नहीं है, जैसा कि कई राज्यों के चुनाव हो सकते हैं। यह नॉक आउट मुकाबला है 2019 का सेमी फाइनल।

देश के सियासी इतिहास में उत्तर प्रदेश की अहमियत ये आंकड़े ही बता देते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश का काफी लंबा-चौड़ा 7 फीसदी भूभाग है, वहीं यह देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है इसके 20 करोड़ बाशिंदे देश की 16 फीसदी से ज्यादा आबादी हैं। उत्तर प्रदेश एक देश होता, तो यह दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता।

इन आश्चर्यजनक आंकड़ों के बावजूद भारतीय राजनीति पर सूबे का प्रभाव अनुपात से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह 543 सदस्यों की लोकसभा में 80 सांसद भेजता है और 1991 तक भारत के आठ प्रधानमंत्रियों में से सात इसे अपना घर कहते थे। यह आंकड़ा अब 14 में से आठ प्रधानमंत्रियों पर आ गया है और गिरावट का यह रुझान राज्य के लोगों को बुरी तरह सालता है क्योंकि इसका मतलब है नेतृत्व के ऊंची पायदान से नीचे आना. मंच के ऊपर शोभायमान होने की यूपी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही मोदी ने 2014 में वाराणसी से चुनाव लडने का, और फिर चुनाव के बाद गांधीनगर के अपने पुराने गुजराती गढ़ को छोडने का फैसला किया था।

राष्ट्रीय सियासी चकाचौंध से उत्तर प्रदेश का अलग होना 1989 में शुरू हुआ। यह आरक्षण समर्थक मंडल कमिशन के लागू होने के फौरन बाद की बात है, जब मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी नई ताकत से लैस पिछड़ी जातियों की आवाज के तौर पर उभरकर आई थी। इसके नतीजतन दलित समुदाय भी बीएसपी के पीछे लामबंद हो गया, जिसकी अगुआई पहले कांशीराम के और फिर मायावती के हाथ में थी। कांग्रेस यहां 1989 से सत्ता में नहीं आई. वहीं बीजेपी ने पहले 1991 में कुछ वक्त के लिए और फिर 1997 से 2002 के बीच उथलपुथल से भरे साढ़े चार साल में (जब उसके कार्यकाल के दौरान तीन मुख्यमंत्री रहे थे) राज्य सरकार की अगुआई की थी।

यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी की जबरदस्त जीत ने चुनावी पंडितों को हैरत में डाल दिया था. तब जीत के अंतर से क्षेत्रीय से राष्ट्रीय मुद्दों की ओर लंबे वक्त के संभव बदलाव का संकेत मिला था। शायद इसलिए कि मतदाता बीएसपी की हरेक सरकार की पहचान बन चुके कथित भ्रष्टाचार से और सपा की हर

सरकार की खासियत बन चुकी कथित अराजकता से आजिज आ चुके थे। उन्हीं चिंताओं ने मोदी लहर को मजबूत बनाया, जिसे 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगों के बाद शाह के हिंदू ध्रुवीकरण का समर्थन हासिल था।

जिस सोशल इंजीनियर ने यूपी को क्षेत्रीय पार्टियों के लिए देश के प्रमुख जंग के मैदान में बदल दिया था, वह भी 2017 में अपने इम्तिहान से गुजरेगी। 15 साल बाद राज्य उस कगार पर हो सकता है जहां वह राष्ट्रीय मुद्दों को हावी होने दे और सत्ता के गलियारों में फिर एक राष्ट्रीय पार्टी की पदचाप सुनाई दे।

चारों पार्टियों के लंबे चुनाव अभियान न सिर्फ अपने को बचाने की उनकी गहरी इच्छा की झलक देते हैं, बल्कि उस मौके की भी, जो 2019 के आम चुनाव पर अपने असर की वजह से उत्तर प्रदेश का चुनाव देता है। दरअसल, हाल के हफ्तों में सपा को अपने भीतर से जिस विद्रोह का सामना करना पड़ा, वह मुलायम के इस विश्वास से भी उपजा था कि अगर उनकी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटों पर सिकुडने के बजाए बेहतर प्रदर्शन कर पाती, तो वे ज्यादा बड़ी राष्ट्रीय भूमिका निभा रहे हो सकते थे। मुलायम मानते हैं कि बेहतर प्रदर्शन ने उन्होंने 35 के आंकड़े का जिक्र किया था हो सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया होता।

मुलायम के मन में यह बात बिठा दी गई है, जाहिरा तौर पर उनके भाई शिवपाल और चालाक अमर सिंह की ओर से, कि उस हार के लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं। इसी लिए मुख्यमंत्री को हाशिये पर डाल दिया गया है और 'संगठनकर्ता' शिवपाल को पदोन्नति देकर पार्टी के राज्य अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। मुलायम की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा इसलिए और भी बढ़ गई है क्योंकि विपक्ष 2019 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक संघीय मोर्चा बनाने की जद्दोजहद कर रहा है, खासकर जब कोई एक पार्टी अपने दम पर उसे चुनौती दे पाने में सक्षम दिखाई नहीं देती। आपस में जुड़े इन विचारों ने नए सतरंगे गठबंधन के संभावित प्रबल दावेदारों के तौर पर कई नाम उछाले हैं, जिनमें बिहार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ओडिशा से नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, तमिलनाडु से जे. जयललिता और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हैं। 76 वर्षीय मुलायम, जो बिहार में नीतीश-लालू के महागठबंधन से आखिरी वक्त में बाहर आ गए थे, इसे ऐसे एक मोर्चे में शामिल होने, और संभवतः उसकी अगुआई करने, के आखिरी मौके के तौर पर देखते हैं। मुलायम उम्मीद करेंगे कि यादव वोट पार्टी के साथ टिके रहें, अन्य पिछड़े वोटों का भी एक हिस्सा उसके साथ जुड़ जाए, और मुस्लिम सपा को उस अकेली पार्टी के तौर पर देखें जो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को सफलता के साथ नाकाम कर सकती है।

मायावती के लिए तो दांव और भी ऊंचा लगा है. अगर वे मुलायम को धूल चटा सकें, तो उन्हें राष्ट्रीय समीकरण से बेदखल कर सकेंगी और यूपी के उस नेता के तौर पर उभर आएंगी जिसे अन्य विपक्षी नेता अपने साथ लेना चाहेंगे। उस पार्टी के लिए, जो 2012 में यूपी की सत्ता से बेदखल होने के बाद 2014 में लोकसभा की एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी, मायावती 2017 के विधानसभा चुनाव को बीएसपी की प्रासंगिकता कायम करने की गरज से अपने आखिरी मौके की तरह देखती हैं। पांच और साल सत्ता से बाहर रहना कार्यकर्ताओं को मायूस कर सकता है, और राज्य की एक प्रमुख पार्टी के तौर पर बीएसपी के 20 साल लंबे दौर के खात्मे की शुरुआत हो सकती है। मायावती अपने दलित वोट बैंक पर, मुसलमानों की रिझाकर सपा से अपने पाले में लाने पर, और महंगाई, छोटे-मोटे भ्रष्टाचार और रोजगार पर उनके बनिस्बतन फीके रिकॉर्ड को सामने लाकर मोदी से कुछ ब्राह्मण वोटों को झटकने पर निर्भर करके चल रही हैं।

जहां मुलायम और मायावती के पास सोचने के लिए अपना सियासी भविष्य है, वहीं कांग्रेस 2012 में जीती गई अपनी 28 सीटों को बढ़ाने के लिए और खुद को एक ऐसी हालत में लाने के लिए जूझ रही होगी, जहां 2019 के चुनावों के लिए दूसरी विपक्षी पार्टियां उसके साथ जुड़ सकें। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव पहले ऐसे सच्चे चुनाव थे जब राहुल ने राज्य में पूरे समय चुनाव अभियान चलाया था और उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन ने उनकी कुछ चमक उतारने में बड़ी भूमिका अदा की थी। पांच साल बाद अब फिर वैसे ही नतीजे, और वह भी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 44 सीटों के ऐतिहासिक गर्त के फौरन बाद, राहुल गांधी के नेतृत्व की साख को हमेशा के लिए अपूरणीय धक्का पहुंचा सकते हैं।

अमित शाह और बीजेपी के लिए यूपी के चुनाव तय करेंगे कि उनके अगले दो साल कैसे गुजरेंगे। अगर जीते तो पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए अपने पांच वर्षीय कार्यकाल के आखिरी दौर में प्रवेश करते हुए जिंदगी आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर हारे तो न सिर्फ विपक्षी ताकतों बल्कि पार्टी के भीतर भी वरिष्ठ नेताओं के हौसले बुलंद हो जाएंगे। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथों मिली भारी हार ने मोदी की अपराजेयता के आभामंडल को चकनाचूर कर दिया था। बाद में बिहार की हार ने हनीमून के खत्म होने की इत्तिला दी। यूपी में अगर वैसा ही हश्र होता है, तो न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कामकाज पर बल्कि 2019 में उनके दोबारा चुनकर आने की क्षमता पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे।

समस्या कैसी, समाधान है ना।

क्या आपकी कोई समस्या है? क्या आप समाधान चाहते है? तो वर्ल्ड फेम के सम्पादकीय कार्यालय – बी–8 वी. एस. टॉवर, आवास विकास, से.–3ए, सिकन्दरा, आगरा–282007 (उ0प्र0) के पते पर लिखें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का उत्तर ''समस्या कैसी – समाधान है ना'' कॉलम में दें सकें डाक द्वारा अपना प्रश्न/समस्या भेजें लिफाफे के ऊपर ''समस्या कैसी – समाधान है ना'' अवश्य लिखें।

बीजेपी ने छवि सुधारने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। पर उससे ज्यादा पार्टी की कोशिश मुख्यमंत्री हरीश रावत की छवि धूमिल करने की है। यही रणनीति बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन से पहले भी अपनाई थी, लेकिन तब बीजेपी औंधे मुंह गिरी और पार्टी के नेता ही दबी जबान कहने लगे थे कि अब चुनाव में भी रावत को हटा पाना मुश्किल होगा। अगले साल जनवरी-फरवरी में संभावित विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर एक नेता की टिप्पणी पार्टी के अंदरूनी खौफ को भी उजागर करती है। 'पार्टी की कोशिश है कि कम से कम दिल्ली-बिहार विधानसभा चुनाव जैसा हश्र न हो, जहां हमारे सामने पार्टी के बजाए एक व्यक्ति केंद्र बना था और हम उसकी छवि को धूमिल करना तो दूर, अपनी साख भी नहीं बचा पाए थे।'

छवि बदलने को फिर वही पैंतरा

—गौरव तेनगुरिया

राष्ट्रपति शासन के दौरान हरीश रावत यह संदेश देने में सफल हो गए थे कि उनके साथ गलत हुआ है और जनता में भी हमारे बारे में गलत धारणा बनी थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। यह दर्द है मार्च से मई तक उत्तराखंड में चली सियासी उठापटक में रणनीतिकार के तौर पर भूमिका निभाने वाले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का। तख्तापलट की कोशिश में पहाड़ों से गिरकर चोटिल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सहमा हुआ तो है लेकिन उसने उम्मीदों की डोर छोड़ी नहीं है। इसलिए सियासी धोबीपछाड़ में पिछड़ी बीजेपी अब छवि सुधार के साथ-साथ सामाजिक और भौगोलिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर काम कर रही है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान हरीश रावत यह संदेश देने में सफल हो गए थे कि उनके साथ गलत हुआ है और जनता में भी हमारे बारे में गलत धारणा बनी थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। यह दर्द है मार्च से मई तक उत्तराखंड में चली सियासी उठापटक में रणनीतिकार के तौर पर भूमिका निभाने वाले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का। तख्तापलट की कोशिश में पहाड़ों से गिरकर चोटिल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सहमा हुआ तो है लेकिन उसने उम्मीदों की डोर छोड़ी नहीं है। इसलिए सियासी धोबीपछाड़ में पिछड़ी बीजेपी अब छवि सुधार के साथ-साथ सामाजिक और भौगोलिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर काम कर रही है।

अब चुनावी जंग में कोई चूक न हो, सो पार्टी ने मार्च से मई तक चले 'ऑपरेशन लोटस' के मुखिया रहे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को परे रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दो वरिष्ठ नेताओं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया है। प्रधान 2012 के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी रह चुके हैं और राज्य संगठन के नेताओं से वाकिफ हैं तो हिमाचल प्रदेश के नड्डा को पहाड़ की संस्कृति और मिजाज को समझने वाला नेता मानकर शाह ने जिम्मेदारी सौंपी है।

बीजेपी ने छवि सुधारने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। पर उससे ज्यादा पार्टी की कोशिश मुख्यमंत्री हरीश रावत की छवि धूमिल करने की है। यही रणनीति बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन से पहले भी अपनाई थी, लेकिन तब बीजेपी औंधे मुंह गिरी और पार्टी के नेता ही दबी जबान कहने लगे थे कि अब चुनाव में भी रावत को हटा पाना मुश्किल होगा। अगले साल जनवरी-फरवरी में संभावित विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर एक नेता की टिप्पणी पार्टी के अंदरूनी खौफ को भी उजागर करती है। 'पार्टी की कोशिश है कि कम से कम दिल्ली-बिहार विधानसभा चुनाव जैसा हश्र न हो, जहां हमारे सामने पार्टी के बजाए एक व्यक्ति केंद्र बना था और हम उसकी छवि को धूमिल करना तो दूर, अपनी साख भी नहीं बचा पाए थे।'

खैर, बीजेपी ने खास तौर से उन 44 विधानसभा क्षेत्रों में पर्दाफाश यात्रा निकाली जहां उसके विधायक नहीं हैं। इसमें बीजेपी ने उस स्टिंग को खास तौर से दिखाया जिसमें कथित तौर पर रावत अपने कांग्रेस के विधायक से ही वापस लौटने और बदले में मंत्रालय के जरिए कमाने-खाने की छूट देने की बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी खेमे से भी सवाल उठा कि बीजेपी में जाने वाले 10 बागी क्या मुफ्त में गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी आरोप जड़ते हैं, रावत सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है और रावत ऐसे नेता हैं जिन्होंने अलग उत्तराखंड के आंदोलन का विरोध किया था। बलूनी का तंज है, 'सरकार बचाने के लिए रावत ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की थी। अब उसकी भरपाई के लिए हरदा (हरीश रावत) कर, रंजीत (रिश्तेदार) कर, हरीश धामी (विश्वस्त) कर, रेणुका (पत्नी) कर, आनंद (बेटा) कर जनता को हर छोटे-मोटे कामों की एवज में देना पड़ रहा है। बेहतर होगा केंद्र के बनाए जीएसटी की तरह रावत भी सभी को मिलाकर कुटुंब कर शुरू कर दें।'

विधानसभा चुनाव

		2012		2007	
	पार्टी	सीटें	वोट%	सीटें	वोट%
	बीजेपी	31	33.13	34	31.90
	कांग्रेस	32	33.79	21	29.59
	बीएसपी	03	12.19	08	11.76
	यूकेडीपी	01	1.93	03	5.79
	निर्दलीय	03	12.34	03	10.81

इस यात्रा के बाद पार्टी ने कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड अभियान शुरू किया है, जिसमें जिला स्तर पर कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराने की मुहिम छेड़ी गई है। 12 सितंबर को श्रीनगर में करीब डेढ़ सौ कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल कराया गया। यह अभियान चुनाव तक जारी रखने की रणनीति है। राज्य के पांचों लोकसभा क्षेत्र में सैनिक सम्मेलन करने की भी योजना है। इस कड़ी में 1 अक्तूबर को पीठसैण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्य तिथि पर कार्यक्रम है, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर शामिल होंगे। बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य धन सिंह रावत कहते हैं, 'आजादी के बाद पहली बार कोई रक्षा मंत्री इस क्षेत्र में आएगा।' युवा मोर्चे की ओर से सितंबर के आखिर तक 'घेरा डालो, डेरा डालो' अभियान और महिला मोर्चे की ओर से 'हिसाब दो, जवाब दो' कार्यक्रम चल रहे हैं। पार्टी ने गांव चलो अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धि, बूथ संपर्क और रावत सरकार की नाकामी को भुनाने का खाका बनाया है।

उत्तराखंड में 50 फीसदी से ज्यादा की आबादी वाले राजपूत समाज की यहां के समीकरण में अहम भूमिका है। तभी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश शुरू करने पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर दांव खेलने की रणनीति बनाई थी. रावत की तरह कोश्यारी भी कुमाऊं क्षेत्र से और सहज-सरल नेता माने जाते हैं। 70 सदस्यीय विधानसभा में कुमाऊं क्षेत्र की 29 और गढ़वाल की 41 सीटें हैं। बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में कुमाऊं में स्थिति कमजोर दिख रही है क्योंकि मुख्यमंत्री रावत उसी क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस से बगावत करने वाले 10 विधायकों में से 8 गढ़वाल क्षेत्र से थे। सूत्रों की मानें तो बीजेपी का फोकस गढ़वाल क्षेत्र पर ज्यादा

रहेगा इसलिए पार्टी ने इन सभी 10 बागियों को चुनाव में टिकट देने का मन भी बना लिया है. सरकार बनने की स्थिति में पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भविष्य में राज्यसभा भेजा जा सकता है। उनके छोटे बेटे सौरभ बहुगुणा को उनकी विधानसभा सीट सितारगंज से उम्मीदवार बनाया जाना तय-सा है। एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बागियों को टिकट दिया गया तो उन इलाकों में पार्टी को भितरघात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पहले से तैयारी कर रहे कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। बीजेपी के रणनीतिकारों का कहना है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं में नकारात्मक छवि से ही उसका चुनावी समीकरण बिगड़ता है। इसलिए इस बार पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एससी सम्मेलन करने की रणनीति बनाई है।बीजेपी ने ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य के साथ दलित मतदाताओं का सामाजिक गुलदस्ता बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

कांग्रेस के 10 बागियों के आने के बाद बीजेपी में ही चार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और उन्हें मिलाकर मुख्यमंत्री पद के लिए कम से कम 10 दावेदार पैदा हो गए हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, श्श्उत्तराखंड में हमारी पिछली बार की हार की वजह भी अंदरूनी गुटबाजी थी। यह जारी रही तो जीतना असंभव हो जाएगा।' 73 वर्षीय कोश्यारी को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की उम्मीद थी पर रणनीतिक लिहाज से दलित सांसद अजय टम्टा को जगह दे दी गई। दबाव बनाने के लिए आखिरी दांव के तौर पर कोश्यारी ने 2019 में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। पहले भी सतपाल महाराज उनका खुला विरोध कर चुके हैं। कोश्यारी का मानना है कि केंद्रीय संगठन महासचिव रामलाल, संयुक्त संगठन महासचिव शिव प्रकाश और राज्य बीजेपी के संगठन मंत्री संजय कुमार शीर्ष नेतृत्व को जनता की नब्ज के बारे में सही फीडबैक नहीं दे रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री 81 वर्षीय बी.सी.खंडूड़ी की भी शिकायत रही है कि सरकार में इस्तेमाल नहीं किया जाना था तो 75 की उम्र पार करने वालों को लोकसभा टिकट ही क्यों दिया गया। और रमेश पोखरियाल निशंक ने तो, सूत्रों के मुताबिक, अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें उत्तराखंड का सर्वाधिक विकास उनके मुख्यमंत्रित्व काल में होने का दावा था। हालांकि बीजेपी के अंदरूनी सर्वेक्षणों में अब भी खंडूड़ी पहली तो कोश्यारी दूसरी पसंद के तौर पर उभरे हैं। पार्टी खंडूड़ी-कोश्यारी को साझा चुनाव की कमान सौंपने की मन बना रही है, पर मुक्चयमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी।

बीजेपी आलाकमान इन नेताओं को एकसूत्र में बांधे रखने के जतन कर रहा है लेकिन वह चौकन्ना भी है कि राज्य के शीर्ष नेताओं की तनातनी में सत्ता फिर कहीं हाथ से निकल न जाए।

खाते में सेंध लग जाए तो
24 घंटे में साइबर सेल को दे सूचना

एक व्यक्ति के माबाइल पर मैसेज आया कि उनके क्रेडिट कार्ड से 90 हजार की शॉपिंग की गई है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि कार्ड उसके पर्स में था और उसने एक रुपये का भी सामान इससे नहीं खरीदा था। लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए साइबर सेल को तुरन्त सूचना दी। नतीजा यह हुआ कि उनके बैंक एकाउंट से निकला पूरा पैसा जाने से बच गया। इसकी शर्त यह है कि शिकायत 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए।

साइबर सेल इसी तरह तीस लाख रुपये खातों में वासप करा चुकी है। अगर आपके साथ ही कभी ऐसा फ्रॉड हो जाए तो आपको 0562-2210551 नंबर डायल करना होगा। यह साइबर सेल का है। 0562 आगरा का एसटीडी कोड है।

साईबर अपराधी बड़ी सफाई से आपसे आपका बैंक एकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड और एटीएम नंबर और पासवर्ड जान लेते हैं। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। हर महीने ऐसे 30-40 मामले सामने आ रहे हैं।

ट्रांनजेक्शन रूकवाकर बचाते है फ्रॉड से

साइबर सेल के अधिकारी बताते हैं कि अगर किसी के एटीएम कार्ड से कैश निकाला गया हो या किसी के बैंक एकाउंट में चेक या कैश जमा कर दिया गया हो तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रॉड करके कार्ड से शॉपिंग की गई है तो जिस कंपनी के ई-वालेट से पेमेंट होना है, उससे ट्रांजेक्शन रूकवा देते है लेकिन यह सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही हो सकता है।

भारत को उकसाना बंद करे पाकिस्तान

—आर.एन. शर्मा

उड़ी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार सैन्य हमलों का विकल्प अपनाने में संकोच नहीं बरता, बावजूद इसके कि इसके बढ़ने की पर्याप्त गुंजाइश थी। जानकार यह दलील दे सकते हैं कि पहली बार भारत ने ऐसा हमला नहीं किया है, लेकिन शायद ही कभी यह इतना व्यापक रहा हो सरहद पार जवाबी वार। न ही कभी ऐसे हमलों का उतना प्रचार किया गया जैसा कि एनडीए की सरकार ने इस बार किया है ताकि पाकिस्तान और विश्व को एक कड़ा संदेश जाए कि अब बहुत हो चुका। साथ ही घरेलू आक्रोश को भी थामा जा सके, जो उड़ी हमले के बाद पैदा हुआ है जिसमें 19 फौजी मारे गए थे।

बोआ कंस्ट्रिक्टर दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक विशाल अजगर है, जो अपनी गुंजलक में अपने शिकार को चौतरफा जकड़कर उसका दम घोंट देता है। जनरल अयूब खान से लेकर अब तक पाकिस्तान के तमाम नेताओं के मन में यह डर रहा है कि कश्मीर को बलपूर्वक छीनने की उनकी महत्वाकांक्षाओं के जवाब में भारत कहीं यही रणनीति न अपना ले।

भारत ने कश्मीर में हुए तमाम उकसावों के जवाब में जब कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य जैसी तमाम रणनीतियों के रास्ते पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ना चालू किया, तब पाकिस्तान को चलाने वाले दोनों शरीफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और फौज के मुखिया राहील शरीफ को वैसे ही घुटन का एहसास हुआ होगा, गोया वे किसी बोआ की जकडन में हों। खासकर 28-29 सितंबर की दरम्यानी रात आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए नियंत्रण रेखा के पार भारतीय फौज द्वारा किए गए साहसिक सर्जिकल हमलों ने इस एहसास को पुख्ता किया होगा, जिससे इस्लामाबाद इसका खंडन करने को मजबूर हुआ।

प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे कठिन विदेश नीति संबंधी चुनौती के समक्ष नरेंद्र मोदी ने ऐसी रणनीति अपनाई, जिसे निर्भीक, बहादुराना और उक्वदा ही कहा जा सकता है। यह कदम इसलिए निर्भीक था क्योंकि कश्मीर जुलाई में जिस तरह भारत के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था और पाकिस्तान ने भारत को पीछे की ओर धकेल दिया था, मोदी ने उसी वक्त आक्रामक तेवर अपनाया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का मसला उठा दिया और फिर चीन में समूह-20 की बैठक में दुनिया भर के नेताओं के सामने आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने का काम किया और संयुक्त राष्ट्र में उसके कश्मीर का मसला उठाए जाने पर पानी फेर दिया।

यह बहादुराना इसलिए था क्योंकि उड़ी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार सैन्य हमलों का विकल्प अपनाने में संकोच नहीं बरता, बावजूद इसके कि इसके बढ़ने की पर्याप्त गुंजाइश थी। जानकार यह दलील दे सकते हैं कि पहली बार भारत ने ऐसा हमला नहीं किया है, लेकिन शायद ही कभी यह इतना व्यापक रहा हो सरहद पार जवाबी वार। न ही कभी ऐसे हमलों का उतना प्रचार किया गया जैसा कि एनडीए की सरकार ने इस बार किया है ताकि पाकिस्तान और विश्व को एक कड़ा संदेश जाए कि अब बहुत हो चुका। साथ ही घरेलू आक्रोश को भी थामा जा सके, जो उड़ी हमले के बाद पैदा हुआ है जिसमें 19 फौजी मारे गए थे।

यह कदम उम्दा इसलिए था क्योंकि मोदी ने तब एक ऐसी रणनीति पर काम करना शुरू किया था, जिसमें थ्योडोर रूजवेल्ट के इस उद्धरण की छवि दिखाई देती थी: 'प्यार से बोलो और लंबा डंडा लेकर चलो।' विदेश नीति की अपनी इस शैली का विवरण देते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था, 'किसी भी संभावित संकट से पहले ऐसा किया गया तो यह कदम उत्कृष्ट सोच और निर्णायक कार्रवाई का नमूना होता है।'

मोदी और उनकी टीम ने पर्याप्त दूरदर्शिता दिखाई और कड़ी कार्रवाई की, जब उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान की आक्रामकता की एक सतर्क और सधी हुई प्रतिक्रिया तैयार की। उन्होंने हमला करने से पहले शतरंज पर सभी मोहरे सही जगहों पर बैठा दिए और उसके बाद इच्छित लक्ष्य को हासिल किया। इस दौरान मोदी प्यार से बोलते रहे. केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने उड़ी हमले के बाद पहली बार मुंह खोला और जंग की संभावना को नकारते हुए उड़ी के दोषियों को सबक सिखाने का अधिकार अपने पास बनाए रखा। अपने बेहतरीन नेतृत्व का इस्तेमाल करते हुए मोदी ने पाकिस्तान की अवाम और आतंक को पनाह देने वाले उसके हुक्मरानों के बीच एक लकीर खींचते हुए वहां की जनता का आहवान किया कि वह 'गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ जंग में' उनके साथ आए।

इसके बाद मोदी ने अपना लंबा डंडा घुमाया। संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भेजने के बाद मोदी ने 1960 की सिंधु नदी जल संधि की समीक्षा की बात की। इसे रद्द करने की बात करने के बजाए उन्होंने यह संभावना जताई कि भारत जब चाहे तब नदी के पानी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर सकता है। ऐसा लगा कि उन्होंने कोझिकोड में जो कहा था, यह उससे उलट है क्योंकि पानी एक ऐसा मसला था जो पाकिस्तान की जनता को प्रभावित कर सकता था। एक अधिकारी इस बारे में समझाते हैं, श्प्रधानमंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे तो वे आपको सजा नहीं देंगे। उन्होंने पाकिस्तान से भारत के व्यापारिक संबंध की समीक्षा की भी बात की, जिसमें सबसे पसंदीदा देश का दरजा भी शामिल था।

इसके बाद मोदी ने नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए इस्लामाबाद में होने वाले दक्षेस सम्मेलन में जाना रद्द कर दिया। इसके बाद भारत ने दक्षेस के दूसरे सदस्यों नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका को भी यह ऐलान करने के लिए राजी कर लिया कि वे भी उसमें नहीं जा रहे। इसका संदेश साफ था: पाकिस्तान अकेले भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र को उससे दिक्कत है।

मोदी ने जब सेना का इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो उन्होंने ऐसा विकल्प चुना जिससे जंग भड़कने की न्यूनतम संभावना थी. दो विकल्पों में पहला यह था कि 1971 की तर्ज पर पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाए। इन्हें बाहर रखा गया क्योंकि इनसे एक परमाणु जंग की गुंजाइश बनती थी। एक अन्य विकल्प मिसाइल से हमला करके हाफिज सईद जैसे आतंकियों को खत्म किया जाना था।

यह काफी जोखिम भरा था और यह पाकिस्तान को उकसा सकता था। मोदी ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल हमले का विकल्प चुना क्योंकि पहले भी एलओसी के आरपार हमले हो चुके थे और दोनों फौजें इसकी आदी थीं, जिससे बात आगे नहीं बढ़ती थी।

पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के बाद मोदी ने उसे यह संकेत दिया कि उन्होंने भले ही निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ निबटने के कायदों को बदल डाला है, लेकिन वे अब भी रिश्ते सामान्य करने को तैयार हैं, बशर्ते वह भारत को उकसाना बंद करे। एलओसी पार हमले के ऐलान को काफी सतर्कता के साथ सधे हुए शब्दों में किया गया ताकि यह बताया जा सके कि आतंकी समूहों पर कड़ा हमला बोलने के बाद अब भारत की मंशा तनाव को और बढ़ाने की नहीं है। देश मोदी के पीछे मजबूती से खड़ा था, यहां तक कि विपक्षी दल भी हमले को समर्थन दे रहे थे। जैसा कि एक आला अधिकारी ने बताया, 'हमने संयम की नहीं, रणनीतिक उदासीनता की नीति को त्यागा है। हमने पाकिस्तान में कड़ा संदेश भेजा है कि हम कड़े तरीके से और सकारात्मक रुख से अपनी शर्तों को रख रहे हैं। अगर वे आगे आते हैं, तो हम और ज्यादा खुलने को तैयार हैं संपर्क, संचार, यहां तक कि हम उन्हें बिजली भी बेच सकते हैं। अगर वे सोचते हैं कि वे आतंकवाद की नीति को कायम रख पाएंगे, तब तो उसकी कीमत चुकानी होगी।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया काफी नरम है। वहां की फौज और सरकार दोनों ने ही हमले का खंडन किया है, हालांकि सिलसिलेवार कैबिनेट बैठकें कर रहे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और फौज की स्ट्राइक कोर तक फौज प्रमुख के दौरे से साफ है कि संदेश उन तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान कुछ हद तक जवाब देगा, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों शरीफों के बीच सत्ता का टकराव है और फौज प्रमुख, जो रिटायर होने वाले हैं, अपना सेवा विस्तार चाहते हैं। इसीलिए कश्मीर में हुए आतंकी हमले और पिछले हफ्ते बारामूला का हमला अपेक्षित था, लेकिन जानकारों की मानें तो असली चिंता देश भर में, खासकर नागरिक आबादी के बीच बड़े हमलों को लेकर है। इससे शुरू में सीमित स्तर पर जंग भड़क सकती है, जो भारत निभा ले जाएगा लेकिन हमेशा यह खतरा बना रहेगा कि कहीं यह नियंत्रण से बाहर न चली जाए। यह बात अलग है कि अफगानिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों से लड़ रही पाकिस्तानी फौज को इस वक्त भारत के साथ एक और मोर्चा खोलना भारी पड़ेगा और वह ऐसा नहीं चाहेगी. चीन को छोड़ दें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम बड़ी ताकतों ने भारत का मजबूती से पक्ष लिया है। बीजिंग भी हालांकि उपमहाद्वीप में बढ़ रहे तनाव से चिंतित है और बहुत संभव है कि वह पाकिस्तान का समर्थन करने के बजाए उससे शांत रहने को कहेगा।

सिंधु के पानी और बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के अलावा मोदी की रणनीति ने एक काम यह किया है कि उसने सिर्फ कूटनीतिक अलगाव या सैन्य हमलों से इतर कई किस्म के विकल्पों को सक्रिय करने की जगह बना दी है। अफगानिस्तान, यूएई, ईरान और सऊदी अरब के करीब जाकर भारत दरअसल बोआ अजगर की तरह पाकिस्तान को हमले से पहले घेर रहा है। मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में एक किस्म की अनिश्चितता का तत्व भी समाहित किया है, जिसके चलते पाकिस्तान लगातार कयास लगाने को मजबूर होता रहेगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा। इसके अलावा पाकिस्तान सर्जिकल हमले का खंडन कर रहा है। लिहाजा वह कठोर सैन्य जवाब के लिए तर्क नहीं जुटा सकेगा। अगर उसने एक बार फिर आतंकी हमला किया, तो उससे भारत का ही पक्ष मजबूत होगा।

अगर लक्ष्य यही था, तब तो भारत कामयाब कहा जाएगा। इसका एक प्रतिकूल पक्ष यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत आतंकी हमले को लेकर चौबीसों घंटे सचेत है। पठानकोट और उड़ी में जैसा कि देखा गया, अपने सुरक्षाबलों की निगरानी करने में भारत कमजोर है, इसलिए उसे परिधि पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए तात्कालिक उपाय करने होंगे मजबूत ढाल। कश्मीर लगातार उबल रहा है और पाकिस्तान के साथ बढ़े हुए तनाव से वहां कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए वहां की जनता को जीतने के लिए मोदी को जल्द ही कुछ साहसिक कदम उठाने होंगे। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का फोन पर बात करना एक आश्वस्तकारी संकेत है कि हालात को तनावमुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान के मामले में वे एक फैसलाकुन नेता हैं। अब मोदी को पाकिस्तान के संबंध में कड़ाई और नरमी के बीच की तनी हुई रस्सी पर चलकर दिखाना होगा।

चीन-पाकिस्तान की खतरनाक दोस्ती

—देवेन्द्र कुमार सक्सैना

इसके पीछे उद्देश्य पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते में असंतुलन को दुरूस्त करना है। 'हमारा संबंध मोटे तौर पर सैन्य तक सीमित रहा, लेकिन अब हम एक समूचा नया आयाम इसमें जोड़ रहे हैं। इसलिए पहली बार चीन अपने हजारों इंजीनियरों, मजदूरों और कर्मचारियों को पाकिस्तान में भेजेगा और अरबों डॉलर वहां झोंकेगा। अब चाहे इसे जो कहें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की कामयाबी में भारी निवेश कर डाला है।

माओ त्से तुंग ने उत्तरी कोरिया के साथ चीन के करीबी रिश्ते के बारे में एक बार कहा था कि वह 'उतना ही करीब है जितने होंठ और दांत्य होते हैं। उत्तरी कोरिया दशकों तक चीन का इकलौता साझीदार बना रहा, लेकिन आज बीजिंग में एक नई कहावत चल पड़ी है जिसमें पाकिस्तान को 'बा ताइ' यानी फौलादी भाई कहा जाता है।

हाल के महीनों में चीन ने अहम द्विपक्षीय मसलों पर पाकिस्तान के हित में जिस हद तक पक्ष लेना शुरू किया है, भारत उसे लेकर चिंतित है। यह दो दशक पुराने उस चलन का तकरीबन उलट है जब चीन एक ओर पाकिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते तो दूसरी ओर भारत के साथ नाजुक लेकिन प्रगाढ़ होते रिश्ते के बीच संतुलन साधने की कोशिश में रहता था।

भारत का बाजार उसके पश्चिमी इलाके में सबसे बड़ा है। चीन के जैक मा व वांग जियानलिन जैसे ई-कॉमर्स और रियल स्टेट अरबपति साल में तीन-तीन बार भारत का दौरा करते हैं, न कि पाकिस्तान का। दोनों ही देश चाहते हैं कि उनके बीच आर्थिक रिश्ते समांतर पटरी पर चलते रहें, लेकिन भारत में इन दिनों आम लोगों की राय इसके उलट है। सोशल मीडिया पर चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह 'मेड इन चाइना' के बारकोड की पहचान की जाए।

उड़ी हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और भारत ने चौतरफा प्रतिक्रिया देते हुए नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है, साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग-थलग भी कर दिया है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्तों की हद ही यह तय करेगी कि भारत के प्रयास सफल होते हैं या विफल।

गोवा में 15 अक्तूबर, 2016 को शुरू हो रहे ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होगी, तो पाकिस्तान का साया मंडराता दिखेगा। यह भेंट शी के पिछले भारत दौरे से अलहदा होगी जब सितंबर, 2014 में प्रधानमंत्री ने गुजरात में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था.

मोदी की चीनी चुनौती

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जोर देकर शी तक यह संदेश पहुंचाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सैंकशंस कमेटी में पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को प्रतिबंधित किए जाने के कदम को रोकने की चीन की कोशिश से भारत आहत है. ध्यान रहे कि 30 सितंबर को चीन ने इस कदम को रोकने के लिए मार्च में जताई अपनी तकनीकी आपत्ति को दोहरा दिया था, बावजूद इसके कि कमेटी ने पहले ही अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद को प्रतिबंधित कर डाला था। अब बीजिंग को साल के अंत तक यह तय करना है कि वह अपनी राय को खारिज करता है या उस पर कायम रहता है। बाद वाले विकल्प की ज्यादा संभावना दिखती है।

मोदी की चिंता का एक और विषय 48 सदस्यों वाले परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश की दावेदारी पर चीन का निरंतर कायम विरोध है। जून में सोल में समूह के खुले सत्र में हालांकि चीन का विरोध अनपेक्षित तो नहीं था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने भारत के साथ इसमें पाकिस्तान को शामिल किए जाने का भी खुलकर पक्ष ले लिया. एक अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत था कि चीन दोनों देशों के साथ समान दूरी बनाकर चलना चाह रहा है. बीजिंग ने अपना पक्ष साफ कर दिया जब उसने एनएसजी पर वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधियों को दिल्ली भेजने के बमुश्किल दस दिन बाद उन्हें 23 सितंबर को इस्लामाबाद भी भेज दिया।

आतंक की राजनीति

वैश्विक मान्यता प्राप्त आतंकवादी को चीन का निरंतर समर्थन मोदी सरकार के लिए एक अड़ंगा बन गया है, जिसने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की महत्वाकांक्षा पाली थी, खासकर मई, 2015 में हुई प्रधानमंत्री की उस ऐतिहासिक यात्रा के बाद जिसमें शी ने प्रोटोकश्वल तोड़कर अपने गृह प्रांत शाक्शी में मेजबानी की थी।

भारत की बर्दाश्त की सीमा और समझदारी के दायरे में देखें तो चीन का उसके पुराने सहयोगी को आर्थिक और रणनीतिक समर्थन तथा अजहर का खुलकर लिया गया पक्ष, वह भी भारत में आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में खासकर भारत को बिदकाने वाला है। अतीत में चीन ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जहां भारत के लिए अवरोध पैदा किए हैं, वहीं 2008 के मुंबई हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा के सरगनाओं को सूचीब) करने के कदम का पक्ष लिया था।

इस बार मसला थोड़ा अलग इस मायने में है कि चीन का समर्थन हद से ज्यादा बढ़ गया है। वहां के अधिकारी खुलकर भारत को दोष दे रहे हैं कि प्रतिबंध के रास्ते वह राजनैतिक बढ़त लेने की कोशिश में था, न कि वह देश जिस पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप है।

चीन के उप विदेश मंत्री ली बाओदोंग ने 10 अक्तूबर को कहा, 'आतंकवाद पर दोहरी कसौटी नहीं होनी चाहिए।' संयुक्त राष्ट्र में पूर्व प्रतिनिधि और वरिष्ठ राजनयिक बाओदोंग सैंक्शंस कमेटी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, 'किसी को आतंकवाद विरोध के नाम पर राजनैतिक बढ़त नहीं लेना चाहिए।

जनवरी, 2016 तक चीन में भारत के राजदूत तथा फिलहाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में प्रतिष्ठित फेलो अशोक कंठ कहते हैं कि चीन का समर्थन न सिर्फ पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने का बहाना बन रहा है बल्कि भारत के एक अहम सरोकार को भी नुक्सान पहुंचा रहा है। वे कहते हैं, 'चीन का कूटनीतिक संरक्षण पाकिस्तान को ज्यादा गैर-जिम्मेदार रवैया अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें हमारे सीधे मतलब के मुद्दे हैं जैसे आतंकवाद।' चीन हालांकि इसे दूसरे तरीके से देखता है। जर्मन मार्शल फंड में चीन-पाकिस्तान रिश्तों के जानकार एंड्र्यू स्मॉल कहते हैं, 'अगर वह पाकिस्तान पर अनावश्यक दबाव पड़ता देखेगा तो उसकी पीठ पर हाथ रख देगा।

हाल की घटनाओं ने पहले से ही जटिल भारत-चीन संबंधों को और तनाव में ला दिया है, जिसमें हमेशा से सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच नाजुक संतुलन साधे रहने की जरूरत बनी रही है। दोनों पक्षों ने मोटे तौर पर सीमा

विवाद को नियंत्रण में रखा है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर संलग्नता बनाए रखी है जहां दो दशक से ज्यादा वक्त से एक भी गोली नहीं चली है। दोनों देश विवादित सीमा पर भी परस्पर संलग्नता को विस्तारित करने की दिश में बढ़ रहे हैं। इस साल के आरंभ में पहली बार दोनों देशों की सेना ने एलएसी के करीब संवेदनशील पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में रिलीफ ड्रिल का आयोजन किया। नवंबर के मध्य में दोनों सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी छठवां आयोजन पुणे में किया जाएगा।

भारत के सोशल मीडिया पर सस्ते चीनी माल के बहिष्कार के आह्वान से इतर व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रेलवे, उत्पादन और स्मार्ट शहरों में चीन के निवेश को बढ़कर गले लगा रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि इस साल चीन का भारत में निवेश पिछले एक दशक में हुए 40 करोड़ डॉलर के मामूली निवेश का दोगुना था।

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नाजुक रिश्ते के बीच पाकिस्तान का दोबारा उभार नई चुनौतियां पेश कर रहा है. पूर्व राजनयिक कंठ कहते हैं, 'हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान का पुराना रणनीतिक निवेश है, लेकिन एक बात जो हम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं वह यह है कि उनके रणनीतिक संबंध पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि वह ज्यादा मजबूत हो रहा है। वे कहते हैं, चीन के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्ता अहम है और कुछ लोग तो अब पाकिस्तान को चीन का इकलौता साझीदार भी बताने लगे हैं।

पिछले दो दशक के दौरान चीन और पाकिस्तान ने अक्सर अपने रिश्तों के लिए 'हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा और शहद से मीठा' जैसे मुहावरे का जो इस्तेमाल किया है, वैसा हकीकत में दिखता नहीं है. यह रिश्ता साठ के दशक में काराकोरम हाइवे की ऊंचाइयों पर कायम हुआ था जब दोनों ही देश अपने साझा दुश्मन भारत के खिलाफ जंग में थे। इस रिश्ते का ऐतिहासिक रूप से जबरदस्त रणनीतिक महत्व रहा है, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को मिसाइलें और विमान दिए हैं और परमाणु कार्यक्रम में उसकी नाजायज मदद की है।

नब्बे के दशक में जब चीन की अर्थव्यवस्था खुलने लगी, तो उसने अपने इस पड़ोसी के प्रति रूमानियत वाला भाव छोड़कर सतर्कता और निजी हित का रवैया अपना लिया जो रह-रहकर कुछ समय के भीतर उथल-पुथल का आदी हो चुका था और जिसे खुंजराब दर्रे के पार काफी एहतियात से देखा जाने लगा था। यह बात और ज्यादा साफ हुई भारत के साथ संबंधों के सामान्य होने के बाद, जब राजीव गांधी ने 1988 में चीन का दौरा किया और बीजिंग को यह बात समझ में आ गई कि उसे पश्चिम में स्थित अपने बड़े पड़ोसी से रिश्ते सुधारने ही होंगे और ऐसा करने के लिए उसे ऐसी छवि कायम करनी होगी जिसे एक अधिकारी भारत और पाकिस्तान के साथ बेहतर संतुलन का नाम देते हैं।

चीन के अंदरूनी लोग हालांकि बताते हैं कि दो दशक पुराना यह रणनीतिक बदलाव' अब एक निर्णायक मोड़ पर हो सकता है, जब चीन एक बार फिर अपने पुराने साझीदार की ओर झुकने लगा है। अफसरों का कहना है कि इस बदलाव के संकेत 2009 में ही मिलने लगे थे जब पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य और वित्तीय देनदार अमेरिका ने अफगानिस्तान से खुद को समेटना शुरू किया था। अमेरिका 'आतंक के खिलाफ जंग' में पाकिस्तान को अपना आवश्यक साझीदार मानता था, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही खुद को समेटना शुरू किया, चीन ने दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी।

सीपीईसी का मामला

चीन में शी की नई सरकार के 2013 में आने के फौरन बाद पाकिस्तान में नाटकीय तरीके से उसकी दावेदारी बढनी शुरू हो गई। उसी साल शी ने कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी को बताया कि उनका जोर 'परिधिगत कूटनीति' पर होगा, जिसकी शुरुआत प्राचीन सिल्क रूट की बहाली की एक योजना से की जाएगी जिसके लिए मध्य एशिया में जमीन की एक 'पट्टी' निर्मित की जाएगी तथा हिंद महासागर तक 'समुद्री सिल्क रोड' बनाई जाएगी। शी ने फैसला किया 'बेल्ट ऐंड रोड' नाम की इस योजना के केंद्र में पाकिस्तान होगा क्योंकि जमीन और समुद्र की पट्टी, दोनों ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित बंदरगाह ग्वादर में जाकर मिलेगी, जिसका प्रबंधन चीन के पास आ चुका था क्योंकि भारी नुक्सान का हवाला देकर सिंगापुरी प्रबंधक उसे छोड़ कर जा चुके थे।

अगले दशक में चीन इस कथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को पूरा कर लेगा जो चीन के पश्चिमी शिंजियांग प्रांत के काशगर को ग्वादर के साथ जोड़ेगा और जिसके अंतर्गत 35 अरब डॉलर के ऊर्जा सौदे तथा 11 अरब डॉलर की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल होंगी। पेकिंग यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशिया की रणनीतिक जानकार हान हुआ कहती हैं कि **इसके पीछे उद्देश्य पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते में असंतुलन को दुरुस्त करना है। वे कहती हैं, 'हमारा संबंध मोटे तौर पर सैन्य तक सीमित रहा, लेकिन अब हम एक समूचा**

चीन का समर्थन न सिर्फ पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने का बहाना बन रहा है बल्कि भारत के एक अहम सरोकार को भी नुक्सान पहुंचा रहा है। वे कहते हैं, 'चीन का कूटनीतिक संरक्षण पाकिस्तान को ज्यादा गैर-जिम्मेदार रवैया अपनाने को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें हमारे सीधे मतलब के मुद्दे हैं जैसे आतंकवाद।' चीन हालांकि इसे दूसरे तरीके से देखता है। जर्मन मार्शल फंड में चीन-पाकिस्तान रिश्तों के जानकार एंड्र्यू स्मॉल कहते हैं, 'अगर वह पाकिस्तान पर अनावश्यक दबाव पड़ता देखेगा तो उसकी पीठ पर हाथ रख देगा।

नया आयाम इसमें जोड़ रहे हैं। इसलिए पहली बार चीन अपने हजारों इंजीनियरों, मजदूरों और कर्मचारियों को पाकिस्तान में भेजेगा और अरबों डॉलर वहां झोंकेगा। अब चाहे इसे जो कहें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की कामयाबी में भारी निवेश कर डाला है।

चीन को पाकिस्तान की जरूरत क्यों है

चीन सीपीईसी से दो हित पूरा होते देखता है: अपने करीबी सहयोगी की बिखरती अर्थव्यवस्था में जान फूंकना, जो बदले में चीन के लिए एक स्थिर पश्चिमी परिधि बनाएगा। साथ ही अपने उद्यमों के लिए एक नई जगह मुहैया कराना ताकि उनकी परियोजनाओं को एकमुश्त तट पर ले जाया जा सके, जो चीन में क्षमता की अधिकता से जूझ रहे हैं। चीन के नियोजकों के लिए इस परियोजना का एक रणनीतिक मूल्य भी है, क्योंकि यह ऊर्जा के आयात के लिए अरब सागर तक उसकी पहुंच बनाएगा, जिसके चलते मलक्का जलडमरूमध्य से उसकी जान छूटेगी लंबे समय से उसके मन में यह आशंका है कि कोई प्रतिद्वंद्वी ताकत मलक्का के संकरे मार्ग को बाधित करके चीन की अर्थव्यवस्था को कहीं बंधक न बना ले।

सीपीईसी सिर्फ हवाई मामला नहीं है, यह साबित करने में चीन के अफसर काफी मशक्कत करते हैं। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास में मिशन के उप प्रमुख झाओ लिजियान के मुताबिक, 14 अरब डश्वलर का पहले ही 30 'अर्ली हारवेस्ट' यानी जल्दी नतीजे देने वाली परियोजनाओं में निवेश किया जा चुका है, जिनमें 16 निर्माणाधीन हैं। इनमें अधिकतर ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जिनका लक्ष्य पाकिस्तान में गहराते ऊर्जा संकट को कम करना है। इनमें सहीवाल में बन रहा कोयला आधारित एक पावर प्लांट है जो जून में चालू हो जाएगा। कराची-लाहौर एक्सप्रेस-वे पर सुक्कर-मुलतान वाले खंड में स्थित करोट में बन रहा एक बांध है तथा काराकोरम हाइवे का दूसरा चरण शामिल है जो थकोट से खैबर पक्चतूनख्वा के हवेलियां तक जाएगा।

बेल्ट ऐंड रोड और सीपीईसी के लिए चीन नए वैश्विक वित्तीय संस्थान भी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके तहत वह 40 अरब डॉलर का सिल्क रोड फंड और 100 अरब डॉलर का एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गठित करेगा, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार खुद चीन होगा जिसका योगदन इसमें एक-तिहाई होगा। भारत इसमें दूसरा बड़ा हिस्सेदार है जिसने 8 अरब डॉलर की वचनबद्धता जाहिर की है। भारत की निगाह यह तय करने में है कि इस बैंक में उसका और अन्य देशों का यह दावा शामिल हो कि कैसे यह नया बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के बरअक्स चलाया जाएगा। एआइआइबी की आरंभिक परियोजनाओं में 30 करोड़ डॉलर की लागत से पाकिस्तान में बनाया जा रहा एक मोटर वे है जो सीपीईसी का ही हिस्सा है।

यहां तक कि अफगानिस्तान में भारत की तरह ही चीन भी तालिबान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है और बुनियादी ढांचे और विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थिर माहौल चाहता है। बीजिंग ने संयुक्त परियोजनाओं पर काम करने के लिए दिल्ली से बात भी की है। इससे पड़ोसी देशों में धीरे-धीरे आपसी भरोसा कायम करने का मौका मिल सकता है। बीजिंग को यह भी पता है कि दोनों ही क्षेत्रों में पाकिस्तान के हित स्थिरता लाने में नहीं, बल्कि अस्थिरता पैदा करने में निहित हैं। चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज के निदेशक लांग जिंगचुन कहते हैं, 'भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याएं चीन की समस्या नहीं है। चीन तो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की बेहतरी का स्वागत करता है और उनकी समस्याएं हल करना चाहता है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान और भारत, दोनों के साथ उसके रिश्ते मजबूत हों. सीपीईसी सिर्फ चीन और पाकिस्तान की परियोजना नहीं है, बल्कि भविष्य में इसे भारत, ईरान और अफगानिस्तान तक बढ़ाया जा सकता है, और संबंधित देश अगर आपसी विवाद व मतभेद दूर कर सकें तो उससे पूरे क्षेत्र को इससे फायदा होगा। चीन सीपीईसी के जरिए भारत के प्रति किसी दुष्चक्र का इरादा नहीं रखता है।

चीनी अधिकारियों का कहना है कि सीपीईसी का लाभ आखिर में अकेले पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि भारत और समूचे क्षेत्र को होगा, क्योंकि यह पाकिस्तान को स्थिर करने में मदद कर रहा है. वे इस बात पर जोर देते हैं कि चीन की प्राथमिक दिलचस्पी अपने पड़ोस में स्थिरता कायम करना है जो निवेशों के कामयाब होने की पूर्वशर्त है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के शब्दों में, 'इसीलिए यह आखिर में भारत को भी लाभ पहुंचाएगा।

सैन्य आयाम

चीन के गणित में भारत का बाजार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बीजिंग को अच्छी तरह पता है कि भारत का बाजार उसके पश्चिमी इलाके में सबसे बड़ा है। चीन के जैक मा व वांग जियानलिन जैसे ई-कॉमर्स और रियल स्टेट अरबपति साल में तीन-तीन बार भारत का दौरा करते हैं, न कि पाकिस्तान का। दोनों ही देश चाहते हैं कि उनके बीच आर्थिक रिश्ते समांतर पटरी पर चलते रहें, लेकिन भारत में इन दिनों आम लोगों की राय इसके उलट है। सोशल मीडिया पर चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह 'मेड इन चाइना' के बारकोड की पहचान की जाए।

पूर्व राजदूत कंठ का कहना है कि यह दोनों देशों के सामने एक चुनौती पेश करता है कि दिनोदिन जटिल होते जा रहे रिश्ते को कैसे संभाला जाए। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण कारक बन जाने से यह काम और भी मुश्किल हो गया है। कंठ के मुताबिक, 'चीन भी दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने का इच्छुक है। हम उससे यही चाहते हैं कि वह हमारे सरोकार पर गौर करे। वे कहते हैं, 'भारत-चीन संबंधों को लेकर घटनाक्रम थोड़ा विषाक्त होता जा रहा है। यह दोनों ही देशों के लिए वांछनीय नहीं है। गोवा में मोदी और शी जब मिलेंगे तो दोनों के लिए इस स्थिति को बदलना शायद सबसे महत्वपूर्ण काम होगा।

पोलिटिकल वर्ल्ड

विश्व की 10 सबसे ताकतवर सेनाएं

भारत का स्थान जान आपको भी गर्व महसूस होगा

—के.जी. सक्सैना

दुनियाभर की सेनाओं पर नजर रखने वाली जानी-मानी एजेंसी ग्लोबल फायरपावर ने 2016 की दुनिया की सबसे पावरफुल सेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि ग्लोबल फायरपावर विश्व की जानी-मानी एजेंसियों में शुमार है जो हर वर्ष विश्व के तमाम देशों की सेनाओं को उनकी क्षमता के आधार पर रैंक देती है। आज हम आपको ग्लोबल फायरपावर की लिस्ट के आधार पर विश्व की 10 सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी के बारे में बताने जा रहे हैं। इन देशों की लिस्ट में हाल ही में आतंकवादियों के विरुद्ध सफल सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली भारतीय आर्मी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय आर्मी समेत जानें और किन देशों की आर्मी है टॉप 10 में शामिल।

★विश्व शक्ति अमेरिका को ग्लोबल फायरपावर ने अपनी लिस्ट में पहला स्थान दिया है। अमेरिका का कुल रक्षा बजट 581 अरब डॉलर का है। अमेरिका के पास 8848 टैंक, 2785 लड़ाकू विमान, 13 युद्धपोत, 957 अटैक हेलिकॉप्टर और 75 पनडुब्बी हैं। अमेरिका की सेना में 14 लाख सैनिक हैं।

★रूस को इस सूची में दूसरा स्थान दिया गया है। रूस का कुल रक्षा बजट 46 अरब डॉलर का है। इस देश के पास 15398 टैंक, 1438 लड़ाकू विमान, 1 युद्धपोत, 478 अटैक हेलिकॉप्टर और 60 पनडुब्बी हैं। रूस की सेना 7 में लाख से अधिक सैनिक हैं।

★इस लिस्ट में तीसरा स्थान चीन को मिला है. चीन का कुल रक्षा बजट 155 अरब डॉलर है। चीन के पास 9185 टैंक, 3158 लड़ाकू विमान, 1 युद्धपोत, 200 अटैक हेलिकॉप्टर और 68 पनडुब्बी हैं। चीनी सेना में 23 लाख सैनिक हैं।

★ग्लोबल फायरपावर ने अपनी लिस्ट में चौथा स्थान भारत को दिया है। भारत का कुल रक्षा बजट 40 अरब डॉलर का है। भारत के पास 6464 टैंक, 809 लड़ाकू विमान, 2 युद्धपोत, 19 अटैक हेलिकॉप्टर और 14 पनडुब्बी हैं। भारतीय सेना में लगभग 14 लाख जवान शामिल हैं। भारत की यही सैन्य ताकत उसे विश्व की सबसे चौथी ताकतवर सेना बनाती है।

★फ्रांस को ग्लोबल फायरपावर ने 5वां स्थान दिया है। इस देश का कुल रक्षा बजट 35 अरब डॉलर का है। फ्रांस के पास 423 टैंक, 284 लड़ाकू विमान, 4 युद्धपोत, 48 अटैक हेलिकॉप्टर और 10 पनडुब्बी हैं। फ्रांस की सेना में 2 लाख जवान शामिल हैं।

★ग्रेट ब्रिटेन भी ताकतवर आर्मी वाले देशों की लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है। ग्लोबल फायरपावर ने ब्रिटेन को अपनी लिस्ट में छठे पायदान पर रखा है। ब्रिटेन का कुल रक्षा बजट 55 अरब डॉलर का है। इस देश के पास 407 टैंक, 168 फाइटर प्लेन, 1 युद्धपोत, 49 अटैक हेलिकॉप्टर और 10 पनडुब्बी हैं। ब्रिटेन की सेना में लगभग 1 लाख 50 हजार सैनिक शामिल हैं।

★जापान को ग्लोबल फायरपावर ने अपनी लिस्ट में 7वें पायदान पर रखा है। जापान का कुल रक्षा बजट 40 अरब डॉलर का है। जापान के पास 678 टैंक, 287 लड़ाकू विमान, 3 युद्धपोत, 119 अटैक हेलिकॉप्टर और 7 पनडुब्बी हैं। जापानी सेना में लभगग 2 लाख 50 हजार सैनिक हैं।

★जर्मनी के बाद नंबर आता है तुर्की का, तुर्की इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। इस देश का कुल रक्षा बजट लगभग 18 अरब डूलर का है। तुर्की के पास 3878 टैंक, 207 लड़ाकू जहाज, 64 अटैक हेलिकॉप्टर और 13 पनडुब्बी हैं। तुर्की सेना में लगभग 4 लाख सैनिक शामिल हैं।

★विश्व की जानी मानी सेनाओं में 9वां स्थान ग्लोबल फायरपावर ने जर्मनी को दिया है। जर्मनी का कुल रक्षा बजट लगभग 36 अरब डॉलर का है। जर्मनी के पास 408 टैंक, 169 लड़ाकू विमान, 44 अटैक हेलिकॉप्टर और 5 पनडुब्बी हैं। जर्मन सेना में लगभग 1 लाख 80 हजार सैनिक हैं।

★इटली को ग्लोबल फायरपावर ने अपनी लिस्ट में 10वां स्थान दिया है। ग्लोबल फायरपावर एजेंसी के अनुसार इटली का रक्षा बजट 34 अरब डॉलर का है। इटली के पास 586 टैंक, 158 लड़ाकू जहाज, 2 युद्धपोत, 58 अटैक हेलिकॉप्टर और 8 पनडुब्बी हैं। इटली की सेना में कुल 3 लाख 20 हजार सैनिक शामिल हैं।

इज़राएल में एक गाय जहां सालाना 10,000 लीटर से अधिक दूध देती है, वहीं हमारे यहां गाय औसतन 2,000 से 2,500 लीटर सालाना दूध देती है। साहीवाल, थारपारकर और गीर जैसी भारतीय नस्ल की गायें जरूर बहुत अच्छी मात्रा में दूध देती हैं, लेकिन इस तरह की शु(नस्ल की गायों की संख्या बहुत सीमित है। गांव में आवारा छोड़ दी गई गाएं, इसी बिगड़ी नस्ल की हैं जो कम दूध दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन गायों की सिर्फ नस्ल खराब हुई है, इनके कम दूध देने की एक वजह इनमें पनप रही बीमारियां भी हैं। गाय बड़ी संख्या में आंत की टीबी (जॉनीज टीबी) की शिकार हैं। इस बीमारी के कारण गाय के शरीर को खाना लगता नहीं है। यही नहीं जो देसी गाय पूरे जीवन में 10-12 साल तक दूध दे सकती है, वह दो से तीन बच्चों के जन्म के बाद ही बांझ हो जाती है। इस तरह की गाय को पालने के बजाए आवारा छोड़ देने में ही लोग अपनी भलाई समझ रहे हैं।

बेघर और बीमार हुई बांझ गायें

—सुनील कुमार भटनागर

वैसे तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। 14.63 करोड़ टन लीटर सालाना के दूध उत्पादन के कारनामे में भैंस और गाय की ही मुख्य भूमिका है। 2012 की पशुगणना उठाकर देखें तो पता चलेगा कि देश के 51 करोड़ मवेशियों में से गोवंश की संख्या 19 करोड़ के करीब है। इसमें से बैल-बछड़ों को हटा दें तो गाय की संख्या 12 करोड़ से कुछ अधिक है। संख्या के लिहाज से गाय भैंसों से दोगुनी है। और सिर्फ गांवों की बात करें तो हर गांव में औसतन 306 गाय-बैल बैठते हैं।

वैसे तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। 14.63 करोड़ टन लीटर सालाना के दूध उत्पादन के कारनामे में भैंस और गाय की ही मुख्य भूमिका है। 2012 की पशुगणना उठाकर देखें तो पता चलेगा कि देश के 51 करोड़ मवेशियों में से गोवंश की संख्या 19 करोड़ के करीब है। इसमें से बैल-बछड़ों को हटा दें तो गाय की संख्या 12 करोड़ से कुछ अधिक है। संख्या के लिहाज से गाय भैंसों से दोगुनी है। और सिर्फ गांवों की बात करें तो हर गांव में औसतन 306 गाय-बैल बैठते हैं। लेकिन असल दिक्कत जम्मू-कश्मीर के एनिमल ब्रीडिंग विशेषज्ञ फरहत उमर कुछ इस तरह बताते हैं, 'इज्राएल में एक गाय जहां सालाना 10,000 लीटर से अधिक दूध देती है, वहीं हमारे यहां गाय औसतन 2,000 से 2,500 लीटर सालाना दूध देती है। साहीवाल, थारपारकर और गीर जैसी भारतीय नस्ल की गायें जरूर बहुत अच्छी मात्रा में दूध देती हैं, लेकिन इस तरह की शुद्ध नस्ल की गायों की संख्या बहुत सीमित है। गांव में आवारा छोड़ दी गई गाएं, इसी बिगड़ी नस्ल की हैं जो कम दूध दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन गायों की सिर्फ नस्ल खराब हुई है, इनके कम दूध देने की एक वजह इनमें पनप रही बीमारियां भी हैं। गाय बड़ी संख्या में आंत की टीबी (जॉनीज टीबी) की शिकार हैं। इस बीमारी के कारण गाय के शरीर को खाना लगता नहीं है। यही नहीं जो देसी गाय पूरे जीवन में 10-12 साल तक दूध दे सकती है, वह दो से तीन बच्चों के जन्म के बाद ही बांझ हो जाती है। इस तरह की गाय को पालने के बजाए आवारा छोड़ देने में ही लोग अपनी भलाई समझ रहे हैं। इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए 2014 में टीका विकसित करने वाले मथुरा के केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में पशु स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख डा. शूरवीर सिंह बताते हैं, 'यह बीमारी दूध और गोबर के जरिए भी फैल जाती है। सामान्य तौर पर दूध को उबालने पर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन यह बैक्टीरिया पाश्चरीकरण के बाद भी खुद को बचा लेता है।' डा. सिंह को अफसोस है कि 2014 में भारत सरकार ने उनके टीके को स्वीकार करने के बावजूद बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। उनका मानना है कि ऐसा करने से गायों के बीमार और कम दूध देने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती।

बहरहाल, यह बात तो हुई गायों की उधर, बैल की हालत तो और खराब है। खेती-बाड़ी में अब हल-बैल का इस्तेमाल न के बराबर रह गया है। वे पूरी तरह अनुपयोगी हो गए हैं। पहले उत्तर भारत में आम चलन यही था कि लोग अपने बछड़ों को दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों को बेच देते थे। ये व्यापारी गांव-गांव से बछड़े खरीदते हुए, बड़ा झुंड तैयार करते थे और फिर जुगत भिड़ाकर इन्हें किसी बूचड़खाने तक भेज देते थे। चूंकि बछड़ा आंख के सामने या आस-पास के इलाके में नहीं कटता था, इससे किसान की आत्मा पर गोहत्या का बोझ नहीं पड़ता था और व्यावहारिक रूप से गांव को इस अनुपयोगी पशु का बोझ नहीं उठाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश योजना आयोग के सदस्य सुधीर पंवार कहते हैं, 'इतना तो कहा ही जा सकता है कि उग्र गोरक्षा के कारण लोग बछड़ा बेचने और खरीदने से बचने लगे हैं। गोकशी पहले की तुलना में कम हुई है। लेकिन अनुपयोगी पशुओं से निबटने का दूसरा व्याहारिक तरीका फिलहाल हमारे पास नहीं है। हालांकि 2007 की पशुगणना की तुलना में 2012 की पशुगणना में गाय-बैल की संख्या में मामूली कमी आई है, लेकिन इसमें इसका जिक्र नहीं है कि आवारा गाय-बैल की संख्या घटी है या पहले से बढ़ी है।

गोचर की जमीन पर कब्जे और कांजी हाउस में बीजेपी कार्यालय यहां यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस तरह के गाय-बैल भले ही इनसान के बहुत काम के न हों, लेकिन क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? आखिर जब इनसान और गाय का ऐसा गहरा रिश्ता नहीं रहा होगा, तब भी तो वे अपने हिस्से की जमीन पर विचरती होंगी? असल में हुआ यह है कि बढ़ती आबादी के दबाव में गांवों में गोचर या चारागाह की जमीन बहुत कम हो गई है। जिस जमीन पर मवेशियों को घास चरनी थी, उस जमीन पर अब खेती हो रही है। अगर झांसी की ही मिसाल लें तो जिले में 200 एकड़ जमीन गोचर के नाम पर दर्ज है। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें से ज्यादातर जमीन पर अवैध कब्जे हो गए हैं। किसान नेता शिवनारायण सिंह परिहार बताते हैं कि मायावती सरकार के समय गोचर की जमीन में से ही लोगों को पट्टे भी दिए गए। लेकिन रेवन गांव में इसी तरह के पट्टाधारक कल्लू अहिरवार, घसीटा और सरमन पलट कर सवाल करते हैं, 'हमें सरकार ने पट्टे दिए हैं। वे ग्राम समाज की जमीन पर मिले हैं या गोचर जमीन पर यह सरकार जाने। इसमें हमारी गलती कहां है?' समस्या के व्यापक पहलू पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि देश में 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। पहले इसमें से 10 फीसदी जमीन चरागाह के लिए उपलब्ध थी, इस समय चरागाह के लिए उपलब्ध जमीन घटकर 4 से 5 फीसदी ही बची है। ऐसे में मवेशी पेट भरने के लिए खेतों का रुख करने को मजबूर हैं। और यहीं से इनसान और गाय के बीच तनाव शुरू हो जाता है। इस संघर्ष में गाय का पक्ष लेते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री, गौसेवा, खेमचंद्र शर्मा कहते हैं, 'सरकार को गोचर की भूमि से कब्जे हटाने चाहिए और गोअभयारण्य बनाने चाहिए।'

गायों की दशा

★19 करोड़ मवेशी देश में गोवंश के हैं, इनमें 12.29 करोड़ गाय हैं। ★18.4 करोड़ गोवंश वाले पशु गांवों में रहते हैं, जबकि 71 लाख लोग गोवंश के जानवर शहरी क्षेत्र में हैं। ★306 गांय-बैल औसतन देश की हर गांव में पाए जाते हैं। आवारा पशुओं का अलग से आंकड़ा उपलब्ध नहीं हैं। ★2-3 साल दूध देने के बाद देसी गाय दूध देने के अयोग्य हो जाती हैं, इसकी मुख्य वजह टीबी की बीमारी है। ★10 से 25 साल से ऐसी स्वदेशी तकनीक बनाने में लगेंगे जिससे सिर्फ बछिया पैदा हो विदेशी तकनीक काफी महंगी।

स्रोत : पशु गणना, 2012

वैसे, इस तनाव को घातक होने से बचाने के लिए पहले जानवरों की जेल यानी कांजी हाउस का विकल्प हुआ करता था। इसके तहत यह व्यवस्था थी कि यदि कोई पशु किसी के खेत में घुसता था तो खेत का मालिक उस पशु को कांजी हाउस में बंद करा सकता था। मवेशी के मालिक को जब इसकी जानकारी होती थी तो वह निर्धारित जुर्माना चुकाकर मवेशी को छुड़ा लेता था। कांजी हाउस का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय किया करते थे। झांसी जिले में ही पहले आठ गांव पर एक कांजी हाउस था। लेकिन जैसे-जैसे आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती गई और कांजी हाउस में पशुओं को छुड़ाने वालों का आना कम हो गया तो इनका संचालन कठिन हो गया। इस समय जिले में एक भी कांजी हाउस काम नहीं कर रहा है। सबसे बुरी गत झांसी शहर के कांजी हाउस की हुई। हुआ यह कि 1997-98 में बीजेपी के धन्नूलाल गौतम नगर पालिका के चेयरमैन बने और झांसी सदर से ही बीजेपी विधायक रविंद्र शुक्ला मंत्री बने। दोनों नेताओं के प्रयास से कांजी हाउस की जमीन बीजेपी के जिला कार्यालय के लिए देने का प्रस्ताव नगर पालिका से पारित करा लिया गया। यहां अब बीजेपी का जिला कार्यालय चलता है। शुक्ला बताते हैं, 'कांजी हाउस खंडहर था, वहां बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए हमने पहल कराई थी।' वहीं झांसी के नगर आयुक्त अरुण प्रकाश कहते हैं, 'कांजी हाउस कब और कैसे बीजेपी को दे दिया गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।'

घटनाः 1 झांसी जिले की गरौठा तहसील केसिमरिया गांव के किसान खेतों में घुस रही आवारा गायों से लंबे समय से परेशान थे. तीन साल के सूखे ने उन्हें पहले ही तोड़ दिया था, उस पर इस साल हुई अतिवृष्टि ने उड़द-मूंग की फसल को हलकान कर रखा था। बची-खुची फसल पर आवारा गायों की नजर थी। इसीलिए गांव वाले रात में चौकसी पर बैठ गए। गायों का झुंड खेत में घुसता, इससे पहले ही गांव वालों ने उन्हें खदेडना शुरू कर दिया। जब गांव वालों को तसल्ली हो गई कि उन्होंने रेवड़ को गांव के बाहर खदेड़ दिया है, तभी इससे बड़ी मुसीबत उनके सामने आ गई। गायें अब शाजापुर गांव में घुसने वाली थीं और वहां के लोग भी गायों से उतने ही त्रस्त थे। नतीजा यह हुआ कि गाय तो गई एक तरफ और दोनों गांवों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया. पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन गायों की संख्या और गांव वालों के तेवर देख पुलिस मामले को दबाने के अलावा कुछ न कर सकी।

घटनाः 2 इसी जिले में 18 सितंबर को बबीना के पास ग्राम पंचायत खांडी के केशव राजपूत ने गौर किया कि कुछ गायें एक-दो दिन से अपनी ही जगह पर बैठी हैं। वहां से कहीं गई नहीं। उन्होंने पास जाकर देखा तो सन्न रह गए. गायों के खुर में लंबी-लंबी लोहे की कीलें ठोक दी गई थीं। पैरों में गहरे जख्म हो गए थे। कुछ के जख्मों में कीड़े पड़ गए थे. पूछताछ की तो पता चला कि पास के गांव नयापुरा के राजपूत समुदाय के ही लोग अपनी फसल को इन जानवरों से हो रहे नुक्सान से इस कदर खफा थे कि गोमाता के खुरों में कील ठोकने जैसा क्रूर काम कर बैठे। भारी दबाव के बाद पुलिस ने मामले में एफआइआर दर्ज की।

बुंदेलखंड के एक ही जिले की ये दो घटनाएं, क्या उसी देश में हो रही हैं, जो पिछले एक-दो साल से गोरक्षकों का आतंक देख रहा है। जहां गाय का मांस खाने का इल्जाम चस्पां कर किसी इनसान का कत्ल किया जा सकता है। जहां मरी गाय का चमड़ा उतारने पर दलितों की पिटाई हो रही हो। और हालात यहां तक बिगड़े कि खुद प्रधानमंत्री को दखल देकर कहना पड़ा कि गोरक्षा के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व अपनी दुकान चला रहे हैं। गोरक्षा के ऐसे आक्रामक दौर में गांव वाले आखिर क्यों गोरक्षा के बजाए गोप्रताडना पर उतरने को मजबूर हुए? ये घटनाएं सिर्फ इन्हीं गांवों में नहीं हुई हैं। बुंदेलखंड के किसी भी जिले की पुलिस से पूछ लीजिए, वह आपको बताएगी कि खेत में गाय हांकने को लेकर गांव वालों के बीच झड़प के मामले उनके पास आए दिन आ रहे हैं। इन मामलों में पुलिस गांव वालों को समझा नहीं पाती और गाय को समझाने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। उधर, राजस्थान के नागौर जिले के चितावा थाना क्षेत्र में 11 अक्तूबर को खेत में गाय घुस जाने पर किसान जगदीश ने गोशाला के चरवाहे परमाराम की इस कदर पिटाई की कि उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। वहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा और खिलवानी गांवों में किसान तब आमने-सामने आ गए जब एक गांव के किसान गायों को ट्रैक्टर में भरकर दूसरे गांव में छोड़ गए। इस तरह के हालात से निबटने के लिए गांवों में बाकायदा संघर्ष समितियां बना ली गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अखबारों के स्थानीय संस्करणों में इस तरह की खबरें तकरीबन रोज नजर आ रही हैं।

उत्तर भारत के गांव की बदलती हुई तस्वीर है, जहां लोग गाय को पूजते तो हैं, लेकिन न तो उसे पाल सकते हैं और न अपनी फसल खाने दे सकते हैं। ग्राम समाज और गोमाता के बीच बिगड़ते सुर-ताल को करीब से देखने के लिए इंडिया टुडे ने दिल्ली से मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, बांदा होते हुए इलाहाबाद तक का करीब 1,000 किमी का सफर किया। इस दौरान शहरों में हाइवे पर पसरी गायों से बच कर निकलते वाहन, हाइवे के किनारे घायल या मरी पड़ी गायों के श्य आम थे। कई जगहों पर हालात ऐसे थे, जहां 100 गायों तक के झुंड रात में सड़क पर इस तरह खड़े थे कि उन्हें हटाने के लिए गाड़ी से उतरना लाजमी था। लेकिन सबसे ज्यादा संवेदनशील श्य वे थे जहां गायों के रेवड़ दबे पांव खेतों की ओर कूच करते थे। ऐसे वाकये भी देखने में आए जब उत्तर प्रदेश के इलाकों में गांव वालों ने संभावित विधानसभा प्रत्याशियों के सामने पहली शर्त आवारा गायों से निजात दिलाने की ही रख दी। ये सारे नजारे संकेत दे रहे थे कि उत्तर भारत का ग्रामीण जीवन अब गाय के लिए उस तरह का नहीं रह गया, जहां गोपाल बांसुरी बजा रहे हों और गायें चरना छोड़कर उसे सुनने में तल्लीन हो जाएं। बल्कि वह तो वैसा भी नहीं रह गया जैसा आज से डेढ़-दो दशक पहले तक हुआ करता था। गांव के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, दोनों में ही गाय की अब पहले जैसी भूमिका नहीं रही।

औपचारिकता की गोशालाएं

ग्रामीण जीवन में गोवंश की भूमिका सीमित हो जाने, चरागाह की जमीन के दूसरे काम में इस्तेमाल होने और कांजी हाउस भी खत्म होने के बाद मवेशियों को नियंत्रित करने का एक ही रास्ता बचता है गोशाला। उत्तर प्रदेश में 1967 में जहां 65 गोशालाएं पंजी त थीं, वहीं 2015 में इनकी संख्या बढ़कर 390 हो गई। लेकिन संख्या बढने का मतलब यह नहीं है कि गोशालाएं इतनी सारी गायों की रक्षा कर सकती हैं। अब बांदा का ही उदाहरण लीजिए। पर्यावरण कार्यकर्ता आशीष सागर को आरटीआइ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जिले में नौ गोशालाएं पंजीकृत हैं।

भारत में पाई जाने वाली सामान्य गाएं कई वजहों से बहुत कम दूध दे रही हैं, इससे लोग इन्हे छोड़ रहे हैं।

-पशु प्रजनन विशेषज्ञ

खेती का तेजी से मशीनीकरण होने के कारण बैल की उपयोगिता लगभग समाप्त हो जाना, किसान की बड़ी चुनौती।

-स्वस्थ यूपी योजना आयोग

सरकार को हर हाल में गोचर की जमीन से कब्जे हटाने चाहिए और देशभर में गाय अभयारण्य की स्थापना करनी चाहिए।

-केन्द्रीय मंत्री, वीएचपी

देश में गायों की नस्ल सुधार के साथ ही ऐसी तकनीक पर काम किया जा रहा है, जिससे सिर्फ बछिया ही पैदा हो।

-निदेशक एनडीआरआइ

इन गोशालाओं में कुल मिलाकर 295 गाय-बैल और बछड़े-बछियां हैं। हो सकता है ये गोशालाएं इनकी सबसे अच्छी सेवा करती हों, लेकिन इतने आवारा पशु तो बांदा जिले के चार गांवों के चौराहों पर खड़े मिल जाएंगे। यानी गोशालाओं की क्षमता बहुत ही सीमित है। इसी तरह का हाल लखनऊ के जानकीपुरम इलाके की लक्ष्मण गोशाला का है। नगर निगम ने इस गोशाला के रखरखाव का जिम्मा जीवाश्रय संस्था को दे रखा है। ढाई एकड़ में फैली गोशाला में 650 गाय हैं। नगर निगम यहां गाय के खाने के लिए रोजाना 40 रु. प्रति गाय खर्च देता है। आठ साल से इसी दर से पैसा दिया जा रहा है। इतने पैसे में क्या लखनऊ जैसे शहर में गोसेवा हो सकती है?

और जब गोसेवा नहीं हो सकती तो कई लोग गोसेवा के नाम पर अपनी दुकान चलाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था। स्वयंभू गोरक्षकों के डर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पशु व्यापार ठंडा पड़ गया है। इस साल 20 जून को शामली रेलवे के सामने गोरक्षकों ने गाय से भरे एक मिनी ट्रक को पकड़ लिया। ये लोग कामधेनु योजना के तहत गायें ला रहे थे। इसके बावजूद गोरक्षकों ने इन लोगों की जमकर पिटाई की। बाद में पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। इस तरह की घटनाओं से किनारा करते हुए वीएचपी के केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी कहते हैं, 'हमारे पास गोरक्षक नाम से कोई दल नहीं है। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को गोतस्करी की सूचना मिलती है, तो वे पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं।' महाराष्ट्र में भी गोरक्षा के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए थे। इसके तहत गाय पालने वालों को नियमित अंतराल पर थाने जाकर बताना होता था कि उनके मवेशी की क्या स्थिति है। ऐसा भले ही गोरक्षा के लिए किया गया हो, लेकिन असल में इससे लोग गाय पालन से दूर ही होते चले गए।

गोसेवा की जगह गोसंकट पैदा करने वाले इन उपायों से अलग उपाय सुझाते हुए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के डायरेक्टर ए.के. श्रीवास्तव कहते हैं, 'पहला काम गायों को दुधारू बनाने का है। इसके अलावा सिर्फ बछिया पैदा करने वाली सस्ती तकनीक विकसित करने पर भी रिसर्च चल रही है। इससे बैलों के बोझ से बचा जा सकेगा।' लेकिन क्या अनुपयोगी पशुओं का मांस के लिए उपयोग करना बेहतर विकल्प नहीं होगा? इस सवाल पर श्रीवास्तव कहते हैं, 'मौजूदा पशुओं के लिए ही चारे की कमी है। हमें ज्यादा दूध देने वाले कम पशु चाहिए होंगे।'

व्यक्तित्व विकास के 10 जबरदस्त टिप्स

—हरेन्द्र कुमार सक्सैना

1 अपने ऊपर विश्वास रखें

जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी चाबी है अपने ऊपर विश्वास रखना। अपने ऊपर विश्वास रखना पहला कदम है अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। अपनी काबिलियत पर कभी भी शक ना कीजिये और हमेशा अपने से स्वयं कहें ! मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए है। अच्छी सफलता से जुडी प्रेरक और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ें इससे जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही इससे आत्म सम्मान बढ़ता है और व्यक्तित्व में भी निखर आता है।

2 अपना दिमाग खुला रखें

अपने अन्दर अच्छा व्यक्तित्व विकास लाने का एक और सबसे बड़ा कार्य है अपनी दृष्टिकोण में बदलाव लाना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और अपने दिमाग के बल पर अपना सुझाव या उत्तर दें। अपने फैसलों को खुद के दम पर पूरा करें क्योंकि दूसरों के फैसलों पर चलना या कदम उठाना असफलता का एक मुख्य कारण है।

3 शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता

व्यक्तिगत विकास के लिए शारीरिक भाषा में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। इससे आपके विषय में बहुत कुछ पता चलता है। हर चीज चाहे वह आपका खाने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बात करने का हो या बैठने का तरीका सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। जब भी बैठें सभी चिंताओं को भूल कर आराम से बैठें और जब भी आप किसी से बात करें आंख से आंख मिला कर बात करें।

4 अपने अन्दर सकारात्मक सोच जागृत करें

चाहें आपकी बातें हो या आपके कार्य, सभी जगह सकारात्मक सोच का होना अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे सोचने का तरीका यह तय करता है कि हम अपना कार्य किस प्रकार और किस हद तक पूरा कर सकेंगे। सकारात्मक विचारों से आत्मविश्वास बढ़ता है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। है। जीवन में कई प्रकार की ऊँची-नीची परिस्तिथियाँ आती हैं परन्तु एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा सही नजर से सही रास्ते को देखता है।

5 नए लोगों से जुड़ें

ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिलना और अलग-अलग प्रकार के लोगों से मिलना जीवन के एक नये स्तर पर जाना है। इससे जीवन में संस्कृति और जीवन शैली से जुडी चीजों के विषय में बहुत कुछ सींखने को मिलता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है।

6 एक अच्छा श्रोता बनिए

ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे उत्तर देने के लिए सुनते हैं। क्यों ? सही बात है ना। एक अच्छा श्रोता होना बहुत कठिन है परन्तु यह व्यक्तित्व विकास का एक अहम स्टेप है। जब भी कोई आपसे बात करे, ध्यान से उनकी बातों को सुनें और समझें और अपना पूरा ध्यान उनकी बातों पर रखें। सीधी आँखों से ध्यान दें और इधर-उधर की बातों पर ध्यान ना दें।

7 खुश रहें

दुनिया की हर चीज में खुशी देखने के लिए प्रयास करें। दूसरों के साथ हँसे पर दूसरों पर कभी भी ना हँसे। उल्लासपूर्ण व्यक्ति की हमेशा सराहना की जाती है। हँसना अच्छे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है।

8 विनम्र बनें

भले ही आप प्रतिभाशाली हों, बहुत बड़े व्यक्ति हों परन्तु अगर आपके जीवन में विनम्रता नहीं तो आपका व्यक्तित्व कभी अच्छा नहीं हो सकता। बड़ा अहंकार करने वाले व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता।

ईमानदार और वफादार बनें

कभी भी किसी को धोखा ना दें और भरोसा ना तोड़ें। आपके चाहने वाले आपकी सराहना करेंगे अगर आप ईमानदारी रहेंगे तो। जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है अगर एक बार वह विश्वास टूटा तो भरोसा करना मुश्किल हो जायेगा।

10 मुश्किल की परिस्तिथि में शांति से काम लें

बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व बाहर से देखने में बहुत ही सुन्दर और अच्छा दीखता है लेकिन मुश्किल पड़ने पर उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। इमरजेंसी के समय उनका दिमाग काम नहीं देता और वे हमेशा टेंशन में रहते हैं। ऐसे समय में हार मानाने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अन्दर से कमजोर होता है।

खूबसूरत दिखने के आसान उपाय

—वर्ल्ड फेम न्यूज नेटवर्क

सुंदर दिखना हर किसी की चाहत होती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मंहगे उत्पाद का प्रयोग करें या ब्यूटी पार्लर का रुख करें। चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए जरूरी है कि आप इसका खास खयाल रखें। जानिए कुछ आसान उपाय जिनसे आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी।

झुर्रियों करें दूर

एक चम्मच शहद में कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है।

चमक रखे बरकरार

एक चम्मच गुलाबजल और एक चम्मच दूध के मिश्रण में दो तीन बूंद नींबू का रस मिलाकर इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा की कोमलता व चमक बनी रहती है।

स्क्रबिंग के लिए

टमाटर का टुकड़ा लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें, चेहरे की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। त्वचा को निखारने के लिए स्क्रबिंग बहुत जरूरी है। स्क्रब त्वचा की मृत कोशिकाओं, धूल इत्यादि को हटाकर रोमछिद्रों को बंद होने से रोकता है।

तैलीय त्वचा से पाएं छुटकारा

एक चम्मच नींबू का रस में एक चम्मच गुलाब जल और पिसा हुआ पुदीना मिलाकर 1 घंटे रखें। फिर चेहरे पर लगाकर 20 मिनट बाद धो लें। इससे चेहरे का चिपचिपापन दूर हो जाएगा।

कैसे पाएं निखार

त्वचा में निखार लाने के लिए थोड़े-से चोकर में एक चम्मच संतरे का रस, एक चम्मच शहद व गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। सूखने पर धो डालें।

शहद से पाएं त्वचा में कसावट

चेहरे व गर्दन पर शहद लगाएं थोड़ा सा सूखने के बाद अंगुलियों से चेहरे पर मसाज करें। शहद के सूखने के बाद गुनगुने पानी से इसे साफ करें। इससे त्वचा में कसाव आएगा।

डार्क सर्कल से बचें

आंखों के नीचे झुर्रियां व डार्क सर्कल से बचने के लिए बादाम के तेल में शहद मिलाकर लगाएं और इस हल्के हाथों से मलें और धो लें।

क्लीजिंग के लिए चेहरे से मेकअप को हटाने व धूल मिट्टी से बचाने के लिए क्लीजिंग जरूरी है। इसके लिए चावल के आटे में दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे एवं गर्दन पर अच्छी तरह मलें। इसके बाद चेहरा धो लें।

रुखी त्वचा से बचें

नारियल के तेल में शहद और संतरे का रस मिला लें और इसे रुखी, फटी हुई त्वचा पर लगाएं। इस मिश्रण के सूखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें और हल्के हाथ से पोंछकर नारियल का तेल या कोई और मॉइश्चराइज लगा लें।

यूं हटाएं चेहरे के दाग-धब्बे चेहरे पर काले दागों को हटाने के लिए टमाटर के रस में रुई भिगोकर दागों पर लगाएं इससे काले धब्बे साफ हो जाएंगे।

मुंहासों से पाएं छुटकारा आलू उबाल कर छिलके छील लें और इसके छिलकों को चेहरे पर रगड़ें, मुंहासे ठीक हो जाएंगे।

जय हिन्द-जय किसान
भारतीय लोक न्याय पार्टी जिन्दाबाद

संविधान सभा अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद अमर रहें
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेन्द्र सक्सैना जिन्दाबाद

सबको रोटी सबको न्याय, नहीं होगा अब और अन्याय

एक नये भारत का निर्माण

तब तक सम्भव नही है

1. जब तक देश के एक-एक नागरिक को रोटी, कपड़ा मकान, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़के और रोजगार आदि की बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं होजाती।
2. जब तक देश से भ्रष्टाचार का सफाया नहीं हो जाता।
3. जब तक चुनाव लड़ने के लिए योग्यता अनिवार्य नहीं हो जाती।
4. जब तक जनप्रतिनिधियों/सांसदों/विधायकों/मंत्रियों आदि की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 70 वर्ष निश्चित नहीं की जाती।
5. जब तक राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों का चुनाव सांसद/विधायकों की तरह सीधे जनता द्वारा वोट डालकर नहीं किया जाता।
6. जब तक जातिवाद की राजनीति पर रोक नहीं लग जाती।
7. जब तक नौजवानों को आगे बढ़ने के उचित अवसर नहीं दिये जाते।
8. जब तक महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं की जायेगी।
9. जब तक गांव, खेत-खलियान और किसानों को बरबादी से नहीं बचाया जायेगा।
10. जब तक आम आदमी की रसोई का सामान, तेल, मिर्च-मसाला, आटा, दाल, सब्जी, आदि पूर्ण तय कर मुक्त कर गरीबों को इस कमरतोड़ महंगाई से नहीं बचाया जाता।
11. जब तक शिक्षा व रोजगार को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर नौजवानों को उनके अन्धेरे भविष्य से बाहर नहीं निकाला जाता।
12. जब तक महिलाओं को संसद/विधायकी में कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं मिल जाती।

यदि आप सभी चाहते है नये भारत का निर्माण हो तो भारतीय लोक न्याय पार्टी का साथ दें।

भारतीय लोक न्याय पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण

प्रधान कार्यालय - इन्दिरा नगर, लखनऊ E-mail : blnp.india02@gmail.com

आज प्रत्येक युवक/युवती स्मार्ट, सुन्दर, सैक्सी, दिखना चाहते है वे चाहते है कि हम भी दुनिया के सामने आयें और फिर दुनिया की नजरों में छा जायें, शायद उन्हें दुनिया के सामने आने का अवसर ही नहीं मिल पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ''वर्ल्ड फेम'' न्यूज मैग्जीन देगी आपको दुनिया के सामने आने का मौका ''एक कदम आपका, निन्यानवे कदम हमारे''

आयशा शर्मा की हुई बॉलीवुड में एंट्री

—वर्ल्ड फेम न्यूज नेटवर्क

नेहा शर्मा की बहन का एक म्यूजिक वीडियो 'इक वारी' लॉन्च हुआ है, जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ रोमांस फरमाती नजर आ रही हैं।

बॉलीवुड में एक और एक्ट्रेस की बहन एंट्री मार चुकी हैं और वो हैं 'क्या सुपर कूल हैं हम' व 'यंगिस्तान' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा। उनका एक म्यूजिक वीडियो 'इक वारी' लॉन्च हुआ है, जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ रोमांस फरमाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया है।

वैसे आपको बता दें कि आयशा के लिए ग्लैमर इंडस्ड्री बिल्कुल नई नहीं है। वो एक मॉडल भी हैं और जल्द फिल्म के जरिए भी बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने को लेकर उत्सुक हैं। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'नमस्ते इंग्लैंड' में आयशा के होने की चर्चा है। 'जुड़वा 2' को लेकर भी उनका नाम सामने आया था। वहीं नेहा शर्मा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो इन दिनों 'तुम बिन 2' और 'हेरा फेरी 3' में व्यस्त हैं।

पागलों की तरह प्यार में हूं
सैयामी खेर

—वर्ल्ड फेम न्यूज नेटवर्क

'मिर्जिया' में अनिल कपूर के बेटे के साथ अपनी कैमेस्ट्री को लेकर सुर्खियों में छाई सैयामी खेर ने पहली बार निजी जिंदगी से जुड़ी इतनी बड़ी बात बताई है।

राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'मिर्जिया' से जहां अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं, वहीं इस फिल्म से गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री उषा किरण की पोती और तन्वी आजमी की भतीजी सैयामी खेर भी अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। फिलहाल 'र्मिजिया' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोगों दोनों की तारीफें कर रहे हैं।

खास तौर से हर्षवर्धन के साथ सैयामी की कैमेस्ट्री काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सैयामी ने अपनी रियल लव लाइफ के बारे में भी खुलासा किया है और यह बात स्वीकार की है कि वो एक रिलेशनशिप में हैं। हालांकि उस 'लकी' शख्स का नाम नहीं बताया। सैयामी का कहना है, मैं एक लॉन्ग-टर्म रिलेशनशिप में हूं। मैं पिछले करीब छह सालों से अपने कॉलेज के एक लड़के के साथ पागलों की तरह प्यार में हूं।'

वहीं सैयामी ने यह भी बताया कि वो जिससे प्यार करती हैं, उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, मगर मैं हमेशा प्यार करती रहूंगी और पूरी कोशिश करूंगा कि यह काम कर जाए।'

एमी ने मुर्गियों पर जताया प्यार

—वर्ल्ड फेम न्यूज नेटवर्क

बॉलीवुड अभिनेत्री एमी जैक्सन पेटा ने एक अभियान के दौरान शाकाहार के प्रति जागरूकता लाने के लिए फार्म में पाले जाने वाले जानवरों व मुर्गियों की संरक्षण के रूप में दिखाई दे रही हैं। पीपुल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) भारत के अभियान में एमी चूजे को कंधे पर बैठाए मुस्कराते हुए नजर आईं। साथ ही यह संदेश दिया गया है, 'शाकाहारी लोग चूजों (मुर्गियों के बच्चों) को खुश रखते हैं।' अभिनेत्री का कहना है, 'मांसाहार का सेवन दिल की बीमारियों, कैंसर और मोटापे का कारण बन सकता है। शाकाहारी बनने के बाद से उनके शरीर में परिवर्तन आया है।' बकौल एमी, 'मेरी त्वचा की रंगत अब पहले से ज्यादा साफ हो गई है। मैंनने अपने शरीर में परिवर्तन देखा है। मैंने अपने मेटाबॉलिज्म (चयापचय) में परिवर्तन महसूस किया है। मैं अब पहले से ज्यादा स्वस्थ, सरल और ऊजार्वान महसूस करती हैं।'

गलतियों पर काम करना चाहूंगी : डायना पेंटी

—वर्ल्ड फेम न्यूज नेटवर्क

अभिनेत्री डायना पेंटी ने कहा कि वह रचनात्मक आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं और अपनी गलतियों पर काम करना चाहेंगी। डायना ने बताया, 'अगर किसी की आलोचना बेहद रचनात्मक है, तो क्यों नहीं ? मैं इनके लिए तैयार हूं। आप मुझे कहिए कि आप क्या सोचते हैं ? मैं कहूंगी कि मैं बदलाव पर काम कर सकती हूं।'

डायना ने कहा कि कई लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं और इस मामले में आपको उनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है तथा साथ में यह भी सीखना है कि इससे कैसे सबक लिया जा सकता है ? बॉलीवुड की 30 वर्षीया अभिनेत्री का सोशल मीडिया पर उनके उपनाम 'पेंटी' के लिए काफी मजाक बनाया जाता है।

सोशल मीडिया पर इस प्रकार के मजाक से होने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर डायना ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक स्तर पर आपको नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है। विशेषकर पेशेवर तौर पर, जब आप लोगों की नजरों में होते हैं।

डायना का कहना है कि एक अभिनेत्री होने के नाते इस प्रकार की चीजों को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अभिनेत्री भी इंसान होती है और आप अंत में वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं, जैसा सोचते हैं

★ डी.डी./चैक "वर्ल्ड फेम" के नाम आगरा में देय हो जो संपादकीय/विज्ञापन कार्यालय वर्ल्ड फेम न्यूज बी-9ए वी.एस. टॉवर, से.-3ए, सेन्ट्रल पार्क रोड, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा, आगरा-282007 (उ.प्र.) के पते पर भेंजे।

नोट : आगरा से बाहर के चैक स्वीकार नहीं होंगे।

★ आने वाले अंक की प्राप्ति के लिए कृपया यह सुनिश्चत कर लें कि आपका भुगतान पिछले महीने के प्रथम सप्ताह तक हमारे पास पहुंच जाए।

★ आपके द्वारा भेजी गई सदस्यता राशि (नगद/चैक/ड्राफ्ट) वर्ल्ड फेम के संपादकीय/विज्ञापन कार्यालय में जमा होने के उपरान्त प्रक्रिया में कम से कम एक और अधिकतम दो माह का समय लग सकता है। उसके उपरान्त नियमित पत्रिका भेजी जाती रहेगी।

★ सदस्यता राशि नकद देने से पूर्व यह सुनिश्चत कर लें कि आपसे राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति "वर्ल्ड फेम" का अधिकृत प्रतिनिधि है अथवा नहीं है।

★ कृपया अपना नाम व पता स्पष्ट अक्षरों में लिखें जिस पर जिला/पिन कोड/राज्य/फोन/मोबा. नं./ मेल आदि भी लिखें। सदस्यता राशि संपादकीय विज्ञापन कार्यालय को प्राप्त होने के दिनांक से कम से कम एक माह बाद से ही नियमित रूप से पत्रिका सदस्यों को भेजी जा सकेगी।

★ "वर्ल्ड फेम" किसी भी डाक की विलम्ब, परिवहन क्षति या सदस्यता फार्म पर किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

★ अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिए संपादकीय कार्यालय पर अथवा मो. +91-9410410963 पर सम्पर्क करें।

"वर्ल्ड फेम" न्यूज मैग्जीन

नियमित पढ़ने हेतु आत ही सदस्य बनें।

एक वर्ष के लिए ₹ 360/-

दो वर्ष के लिए ₹ 700/-

तीन वर्ष के लिए ₹ 1050/-

निम्न फार्म भरकर भेंजे

कृपया टिक ☑ करें कि आप अपना सदस्यता शुल्क एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष के लिए भेज रहे है।

एक वर्ष के लिए ☐ दो वर्ष के लिए ☐ तीन वर्ष के लिए ☐

मैं नाम...पुत्र/पुत्री/पत्नी...उम्र..................

व्यवसाय...पता...

....

जिला/शहर.................................राज्य.................................पिन कोड.................................

मोबा. ....ई–मेल...

रू०.................... सदस्यता शुल्क ''वर्ल्ड फेम'' आगरा के पक्ष में डी.डी./चैक नं. ....

दिनांक....................बैंक का नाम...(संलग्न है) भेज रहा/रही हूँ

दिनांक :....................

आवेदक के हस्ताक्षर

(प्राप्ति) यह सिलिप यहां से फाड़कर सदस्य को दें

नाम...पता...

.... से (1)/(2)/(3)......... वर्ष का

सदस्यता शुल्क रू............... नगद/चेक/ड्रॉफ्ट सं.................... बैंक.................................प्राप्त हुआ

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षर

नाम (अधि. प्रतिनिधि) ....पद................................. मो०.................................

पनीर दो प्याजा

— शीतल वर्मा

शेफ के हाथों का जादू घर पर ही चखना चाहते हैं तो लंच या डिनर में ट्राई करें रेस्टोरेंट वाले पनीर मिर्च दो प्याजा का स्वाद।

सामग्रीः-

पनीर 500 ग्राम
1 शिमला मिर्च हरी मिर्च
2 प्याज, सलाइस किया हुआ
सांभर प्याज
2 चम्मच तेल
3 छोटी इलाइची
1 छोटा चम्मच जीरा
1 चम्मच साबुत सूखा धनिया 'कुटा हुआ'
1 चम्मच अदरक-लहसुन की पेस्ट
1 टमाटर
1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच धनिया पाउडर
1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर
3/4 कप दही
नमक स्वादानुसार

विधि :

एक नॉन स्टिक पैन में तेल गरम करने रखें। हरी शिमला मिर्च के सवा इन्च के टुकड़े काटें। पैन में छोटी इलाइची, जीरा, धनिया और स्लाइस किया हुआ प्याज डालें और गहरा सुनहरा होने तक भूनें। अब उसमें सांभर प्याज डाल कर 2-3 मिनट तक भूनें। पनीर को चौकोर टुकड़ों में काट लें। पैन में अब अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालें। उसे अच्छी तरह मिलाकर 2 मिनट तक भूनें। फिर डालें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अच्छी तरह मिलाकर फिर डालें शिमला मिर्च, मिर्च और दही। धीमी आंच पर ढक कर तब तक पकाएँ जबतक शिमला मिर्च और भावनगरी मिर्च नरम हो जाए। अब नमक डाल कर मिला लें। फिर एक चौथाई कप पानी डालें। अब पनीर डालकर हल्के हाथ से मिला लें। धीमी आंच पर ढक कर 5 मिनट तक पकाएं। चपाती के साथ गरमागरम परोसें।

"उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाये।
उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाये।
उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाये" –ओशो

SHIRDI SAINATH

साँई कृपा ना बरसे तो कहना......

मुझे मददगार बनाकर तो देख, तुझे सब की गुलामी से ना छुड़ा दूँ तो कहना।
मेरे लिये कड़वे वचन सुनकर तो देख, तुझे सबसे मीठा ना बना दूँ तो कहना।
मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, तुझे चरित्रवान ना बना दूँ तो कहना।
मेरे लिये कुछ बनकर तो देख, तुझे सब कुछ ना बना दूँ तो कहना।
स्वयं को न्यौछावर करके तो देख, तेरा जीवन अमृत ना बना दूँ तो कहना।
मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मशहूर ना बना दूँ तो कहना।
मेरे लिए आँसू बहाकर तो देख, तेरा जीवन खुशियों से ना भर दूँ तो कहना।
मेरा एक बार ध्यान रखकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूँ तो कहना।
मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर का भण्डार ना खोल दूँ तो कहना।
मेरे लिए मार्ग पर निकलकर तो देख, तेरे लिए हर रास्ता ना खोल दूँ तो कहना।
मेरा एक बार बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूँ तो कहना।
मेरी बात एक बार मानकर तो देख, साँई कृपा ना बरसे तो कहना।

कभी ना भूलें

मीठी यादों को। अपनों को। किसी के अहसान को।
बुरे वक्त को । बुरे वक्त में जो सहारा दे उस इंसान को।

- यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम इस चोट को भूल जाओगे लेकिन यदि तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो तुम इस चोट को कभी नहीं भूल पाओगे।
- दूसरे के अन्दर की बुराईयों को मत देखो उसकी अच्छाईयों को देखो, अपने अंदर की अच्छाईयों को मत देखो अपनी बुराईयों को देखो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, दु:ख नहीं होगा, भय नहीं होगा। .
- आपका मन अशान्त है, आपको कोई दु:ख है, आपको कोई कष्ट है तो साँई नाथ की शरण में जायें।
- आपकी कोई समस्या है, आपको मदद की जरूरत है, चिन्ता कैसी - मैं हूँ ना

\- देवश्री

जय हिन्द-जय किसान ● संविधान सभा अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद अमर रहें ● भारतीय लोक न्याय पार्टी जिन्दाबाद ● मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेन्द्र सक्सैना जिन्दाबाद

देश में सभी समस्याओं की जड़ महंगाई, भूख, गरीबी और बेरोजगारी, हमें मिलकर इसे उखाड़ना है।

सबको रोटी सबको न्याय, नहीं होगा अब और अन्याय

आर्थिक आजादी के साथ जीने का हक, है सबको

भारतीय लोक न्याय पार्टी के सदस्य बनें,
हम देंगे आपको आर्थिक आजादी से जीने का हक....

देश की जनता से अपील–

संसद/विधायकी में सिर्फ शिक्षित योग्य, ईमानदार व अधिकतम 70 वर्ष आयु तक के प्रत्याशी को ही चुनकर भेजें ताकि देश सही से चल सके।

निवेदक :-

भारतीय लोक न्याय पार्टी

www.bharatiyaloknyayparty.in
E-mail : blnp.india02@gmail.com

सुरेन्द्र कुमार सोनी
राष्ट्रीय महासचिव/प्रभारी राजस्थान
मो0 09887463742

RNI NO. UPHIN/2010/31763
Model : LIMG 0104
Megha Shrivastava, Mumbai
क्या आप
संघर्षरत मॉडल है?
तो
LEAD INDIA MODEL'S GROUP (LIMG)
(THE MODELS MANAGEMENT & CASTING GROUP OF INDIA)
में अपना रजिस्ट्रेशन करायें अपना फोटो, बायोडाटा, बाइटल्स स्टेटिस्टिक्स सहित मेल करें।
LIMG
का मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य
1. एल.आई.एम.जी. से जुड़ी देश की ऐसी मॉडल्स जो संघर्षरत है उन्हें उचित प्लेटफॉर्म व सम्मान दिलाना उन्हें देश के विभिन्न फैशन/ब्यूटी/मॉडलिंग शो अथवा आयोजनों आदि में भाग लेने में उनकी मद्द करना।
2. एल.आई.एम.जी. से जुड़ी युवतियों (मॉडलिंग/डांसिंग /एन्करिंग आदि क्षेत्र से) को देश की विभिन्न इवेंट कम्पनियों/ फैशन इण्डस्ट्रीज/फिल्म इण्डस्ट्रीज व अन्य आयोजनों में काम दिलाना।
3. एल.आई.एम.जी. से जुड़ी मॉडल्स आदि को "वर्ल्ड फेम" पत्रिका व वेबसाइट व अन्य माध्यमों से उनकी प्रतिभा की पहचान कराना।
e-mail : limg4youths@gmail.com, www.f.com/leadindiamodelsgroup